वर्ष : 16 ❖ अंक : 114 ❖ पृष्ठ : 08 ❖ मूल्य : ₹ 3.00 ❖ आरएनआई सं. SIKHIN/2006/17890 ❖ www.anugamini.com

सिक्किम से प्रकाशित प्रथम हिन्दी दैनिक

अनुगामिनी

गंगटोक
बुधवार, 01 दिसम्बर 2021

हमेशा के लिए माल्या का इंजतार नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट 3

भारत अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रहा : सीएम केजरीवाल 8

सिक्किम में मुश्किल में बीजेपी नेतृत्व

- नहीं मिल रहे गठबंधन के फायदे
- हो रहा पार्टी को भारी नुकसान

अश्विनी आनंद

गंगटोक, 30 नवम्बर । सिक्किम में 2019 में सरकार परिवर्तन के बाद से ही राजनैतिक माहौल अस्थिरता वाला रहा है। चुनाव में जहां एसकेएम ने 17 सीटें जीती थीं वहीं उस समय सत्तारूढ़ एसडीएफ पार्टी को भी 15 सीटें मिली थीं। इसके बाद राजनीति ने बड़ी करवट ली और एसडीएफ के 10 विधायक जहां बीजेपी में शामिल हो गए वहीं दो ने एसकेएम का दामन थाम लिया। एसडीएफ के खाते में जहां जीत के बाद भी केवल एक सीट बची वहीं बीजेपी बिना जीते ही 10 विधायकों वाली पार्टी बनकर राज्य में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बन गई।

इसे बाद एसकेएम के अध्यक्ष पीएस गोल ने बीजेपी नेतृत्व से संपर्क किया और एसकेएम के और बीजेपी का प्रदेश में गठबंधन हो गया। हालांकि प्रदेश में गठबंधन सरकार में बीजेपी शामिल तो हो गई लेकिन किसी विधायक को मंत्री पद नहीं दिया गया। शुरू में स्थिति तो यह रही कि एसडीएफ से बीजेपी में शामिल होने वाले विधायकों को एसकेएम ने विधानसभा में भी विपक्षी की सीट ही बैठने के लिए दी। हालांकि बाद में यह मुद्दा गौण हो गया।

प्रदेश में बीजेपी और एसकेएम के गठबंधन की सरकार के ढाई साल से अधिक का समय हो गया है लेकिन जो लाभ बीजेपी को गठबंधन सरकार में रहते होना चाहिए था वह नहीं हो रहा है। एसकेएम ने बीजेपी के विधायकों को सलाहकार पद अवश्य दिए लेकिन इससे अधिक लाभ वे कभी नहीं ले सके। एसकेएम ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डीबी चौहान को भी सलाहकार का पद दिया था लेकिन पार्टी आलाकमान के निर्देश पर उन्हें सरकार में सलाहकार के पद से त्यागपत्र देना पड़ा। बताया जाता है कि बीजेपी ने उन्हें स्पष्ट निर्देश दिया कि था वे संगठन में किसी पद पर रहें या सरकार में। इसके बाद उन्होंने सरकार के सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि डीबी चौहान की भी पार्टी में पकड़ मजबूत नहीं रह गई है। सूत्रों का दावा है कि उनकी पार्टी के विधायक ही उनकी बात नहीं मान रहे।

प्रदेश में अगर बीजेपी की स्थिति देखें तो एसडीएफ सरकार में बीजेपी को कागज का शेर कहा जाता था।

हरेराम प्रधान के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के पद पर रहते वे प्रदेश में संगठन के मजबूत नहीं रहने के बावजूद मीडिया में बने रहते थे और सरकार की किसी भी चूक पर उसपर निशाना साधने से नहीं चूकते थे। इसके बाद स्थितियां बदली और श्री प्रधान को स्वास्थ्य कारणों से राजनीति से दूर होना पड़ा। इसके बाद प्रदेश में वर्तमान मुख्यमंत्री पीएस गोले की अध्यक्षता में नई पार्टी का गठन हुआ और इसके बाद से ही वे प्रदेश की राजनीति में छाए रहे। वर्ष 2014 में उनकी पार्टी ने 10 सीटें जीती थी और वर्ष 2019 में उनकी पार्टी ने सरकार बनाने लायक बहुमत हासिल कर लिया। सिक्किम की राजनीति में शुरू से ही एक खास बात रही है कि यहां विपक्ष कभी मजबूत नहीं रहा। पहली बार वर्ष 2019 में मजबूत विपक्ष बना लेकिन वह भी अधिक दिन तक नहीं रहा और कहा जाता है कि बीजेपी वहां पिछले दरवाजे से सरकार में आ गई।

सरकार में शामिल होने के बावजूद उनके विधायकों को कभी मुख्यमंत्री पीएस गोले ने अधिक तवज्जो नहीं दी। कई बार प्रदेश बीजेपी की ओर से सार्वजनिक रूप से भी कुछ ऐसे बयान आए जिससे साफ है कि एसकेएम और बीजेपी में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा। विद्यार्थियों के निलंबन के मामले में बीजेपी ने खुलकर सरकार की आलोचना की लेकिन इसके बावजूद एसकेएम सरकार ने छात्रों का निलंबन वापस नहीं लिया। इससे प्रदेश में बीजेपी की किरकरी भी हुई। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को इस बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश में गठबंधन सरकार को लेकन बहुत अधिक माथापच्ची करने के मूड में नहीं दिखता है और वह चाहता है कि बस यहां गठबंधन की सरकार चलती रहे।

मुख्यमंत्री पीएस गोले भी प्रदेश में बीजेपी नेताओं को तवज्जो नहीं देते लेकिन बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से उनकी हमेशा अच्छी बनती है। वे केंद्रीय योजनाओं को तवज्जो देते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करना नहीं भूलते हैं।

इस सबका सबसे अधिक नुकसान प्रदेश में बीजेपी को हो रहा है। यहां बीजेपी सरकार में रहते हुए भी सरकार से बाहर है। अब स्थिति यह हो गई है कि सरकार का लाभ लेने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता भी एसकेएम में शामिल हो रहे हैं। सत्ता में रहने के कारण एक ओर जहां एसकेएम लगातार मजबूत होती जा रही है वहीं सत्ता में रहने के बावजूद प्रदेश में अवहेलित रहने के कारण बीजेपी लगातार कमजोर हो रही है।

आशाकर्मियों की वित्तीय स्थिति में किया जाएगा सुधार : सीएम

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 30 नवम्बर । अखिल सिक्किम आशा कल्याण संघ और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की संयुक्त पहल पर आज आशा सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया। यहां के मनन भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर शिक्षा विभाग के मंत्री कुंगा नीमा लेख्रचा, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव जैकब खालिंग, स्वास्थ्य विभाग के सलाहकार केबी गुरुंग आदि विशिष्ठ अतिथि थे।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री गोले ने कहा कि यह राज्य में आयोजित प्रथम और ऐतिहासिक सम्मेलन है। इसके लिए उन्होंने आयोजकों को बधाई दी। उन्होंने आशा कर्मियों की ईमानदारी की भी प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आशा कर्मी की सहायता के बिना कोरोना महामारी की प्रथम और दूसरी लहर का सामना कर पाना मुश्किल था।

उन्होंने आगे कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र मेरी उच्च प्राथमिकता में शामिल है। जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वृद्धि और विकास के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री गोले ने साल 2019 से 2021 तक स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यान्वित विभिन्न योजना, नीति और नए पूर्वाधारों के बारे जानकारी दी। उन्होंने आशा कर्मियों की वित्तीय सुधार का भी आश्वासन दिया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य विभाग के सचिव पेंपा टी भूटिया ने कहा कि राज्य में 667 आशाकर्मी कार्यरत हैं। इसके साथ ही आशा के माध्यम से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न योजनाएं लागू की जा रही है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में आशाकर्मियों के द्वारा अन्य गतिविधियों के साथ ही टीकाकरण अभियान में भी सहयोग किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आशाकर्मी स्वास्थ्य विभाग के अभिन्न अंग है। इस अवसर पर संघ की ओर से मुख्यमंत्री को सम्मानित भी किया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के हाथों आठ आशा कर्मियों को भी सम्मानित किया गया।

अपनी आलोचना नहीं पचा पा रही है सरकार : विष्णु दुलाल

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 30 नवम्बर । एसडीएफ ने कहा है कि वर्तमान एसकेएम सरकार की हालत यह हो गई है कि यह अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। मुख्यमंत्री के गोपनीय सचिव विकास बस्नेत की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में यह साफ झलकता है। ये बातें एसडीएफ के प्रचार प्रसार सचिव विष्णु दुलाल ने कही।

दुलाल ने यहां एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि एसकेएम सरकार कुशासन, अप्रजातांत्रिक ढांचे पर चलने वाली, मौजमस्ती करने वाली, सततालोलुप क्रियाकलाप जारी रखे हुए है। जब विपक्ष की एसडीएफ पार्टी सिक्किम की जनता के अधिकार के लिए आवाज उठाती है और सरकार के कार्यशैली का विरोध करती है तो यह उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सरकार हताश हो उठती और आलोचना को नहीं पचा पाती है। मुख्यमंत्री पीएस गोले के गोपनीय सचिव विकास बस्नेत की ओर से जारी बयान में यह साफ झलकता है।

उन्होंने कहा कि एसडीएफ सरकार एवं पवन चामलिंग के नेतृत्व में सिक्किम की कितनी तरक्की हुई थी, विकास कहां तक पहुंचा था और राज्य के लोगों का जीवनस्तर कैसा था यह किसी से छिपा नहीं है। एसडीएफ सरकार में किए गए काम खुद ही बोल रहे हैं। एसकेएम सरकार के ढाई साल के कार्यकाल में सिक्किम की स्थिति काफी खराब हो गई है। एसकेएम सरकार नारे तक ही सीमित है। जनता से किया एक भी वादा उसने पूरा नहीं किया है। एसकेएम सरकार झूठे वादे कर सरकार में आई है और झूठ के ही बल पर इसमें टिका रहना चाहती है। जनता इस झूठ से मुक्ति पाना चाहती है और समय की प्रतीक्षा कर रही है।

राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता फेडरेशन कप सिक्किम में होगी आयोजित : कला राई

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 30 नवम्बर । राज्य में पहली बार 11वां फेडरेशन कप 2022 राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्य और सरकारी खेल संस्थान के करीब 350 बाडी बिल्डर भाग लेंगे। कार्यक्रम का आयोजन बाडी बिल्डर्स एसोसिएशन आफ सिक्किम की ओर से किया जा रहा है।

आज राजधानी गंगटोक के जीरो ख्रवाइंट स्थित एक होटल में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बाडी बिल्डर्स एसोसिएशन आफ सिक्किम की अध्यक्ष तथा जीएमसी पार्षद कला राई ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता आगमी 11 मार्च से 13 मार्च 2022 तक गंगटोक के मनन भवन में आयोजित होगी। इसमें वरिष्ठ पुरुष बाडी बिल्डिंग, वरिष्ठ महिला बाडी बिल्डिंग और महिला-पुरुष फिजिक स्पोर्ट्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता होगी।

सम्मेलन में उपस्थित आईबीबीएफ और डब्ल्यूबीबीएफ के महासचिव चेतन पठारे ने कहा कि सिक्किम बॉडी बिल्डर एसोसिएशन इंडियन बॉडी बिल्डर एसोसिएशन (आईबीबीएफ) से आबद्ध है। यह कार्यक्रम आईबीबीएफ के सहयोग से सिक्किम में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। उनका कहना है कि वह सिक्किम में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लेने के लिए सिक्किम आए हैं।

उन्होंने यहां की तैयारी पर संतुष्टता व्यक्त करते हुए कहा कि सिक्किम बॉडी बिल्डर एसोसिएशन प्रतियोगिता के लिए तैयार है। उन्होंने जानकारी दी कि सिक्किम इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रयासरत है। सिक्किम से स्थानीय टाशी अंगमू लेख्रचा प्रथम सिक्किमी महिला वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक स्पोर्ट्स फेडरेशन में अंतर्राष्ट्रीय महिला निर्णायक के रूप में हैं। सिक्किम के साथ ही पूर्वोत्तर राज्य से विभिन्न एथलीट देश का नाम रौशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम सिक्किम में आयोजित होने पर गर्व महसूस हो रहा है। सम्मेलन को आईबीबीएफ की महासचिव हिरल सेठ ने भी संबोधित किया।

याक्थुंग आयडल के फाइनल में पहुंचे छह प्रतियोगी

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 30 नवम्बर । नियारा प्रोडक्शन, सिक्किम की ओर से आयोजित याक्थुंग आयडल के फाइनल में शीर्ष 6 प्रतियोगियों ने अपना स्थान सुरक्षित किया है। शीर्ष 6 प्रतियोगी आगमी 12 दिसंबर को रानीपुल मेलाटार में आयोजित होने वाली फाइनल प्रतिस्पर्धा में प्रस्तुती देंगे। फाइनल में सिक्किम से सम्मन लिम्बू, सावन लिम्बू, सोहांग लिम्बू और अंजना लिम्बू को जगह मिली है। इसके साथ ही असम की पिंकी बेघा और दार्जिलिंग के आशीष लिम्बू भी फाइनलिस्ट बने हैं।

प्रतियोगिता मानुसा टेक्सटाइल के द्वारा प्रायोजित है। यह प्रतियोगिता एक नवंबर से शुरू हुई है। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में कुल 25 लोगों ने जगह बनाई थी, जहां से 10 लोग सेमीफाइनल में जगह बना पाए। याक्थुंग आयडल में सिक्किम, दार्जिलिंग और असम के लिम्बू भाषी गायक-गायिका सहभागी बने थे। सेमीफाइनल से 6 लोगों को फाइनल के लिए चयनित किया गया है।

कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य लिम्बू जाति की भाषा-संस्कृति तथा गीत-संगीत के संरक्षण एवं विकास में सहयोग पहुंचाना है। इस बार नेपाली संगीतिक क्षेत्र की प्रसिद्ध गायिका सुनीता थेगिम और सिक्किम के गायक सावन लिम्बू और आरएल खांदाक निर्णायक मंडली में हैं।

जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता आयोजित

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 30 नवम्बर । नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) नामची यहां के जिला प्रशासनिक केंद्र के सम्मेलन हॉल में देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण पर जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस अवसर पर दक्षिण जिला के अतिरिक्त जिलाधिकारी (मुख्यालय) अनंत जैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (दक्षिण) रिनजिंग सी राई, शिक्षा विभाग के उप निदेशक ममता सुब्बा, एनवाईकेएस समन्वयक मुस्कान राई और एनवाईकेएस सदस्य उपस्थित थे।

इस अवसर पर समन्वयक मुस्कान राई ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में बोलने के कौशल का विकास करने का अवसर प्रदान करना है, इसके साथ ही नेतृत्व गुणों वाले युवाओं की पहचान कर उन्हें राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में आगे बढ़ने में सक्षम बनाना भी है।

भाषण प्रतियोगिता में सबका साथ, सबका (शेष पृष्ठ ०३ पर)

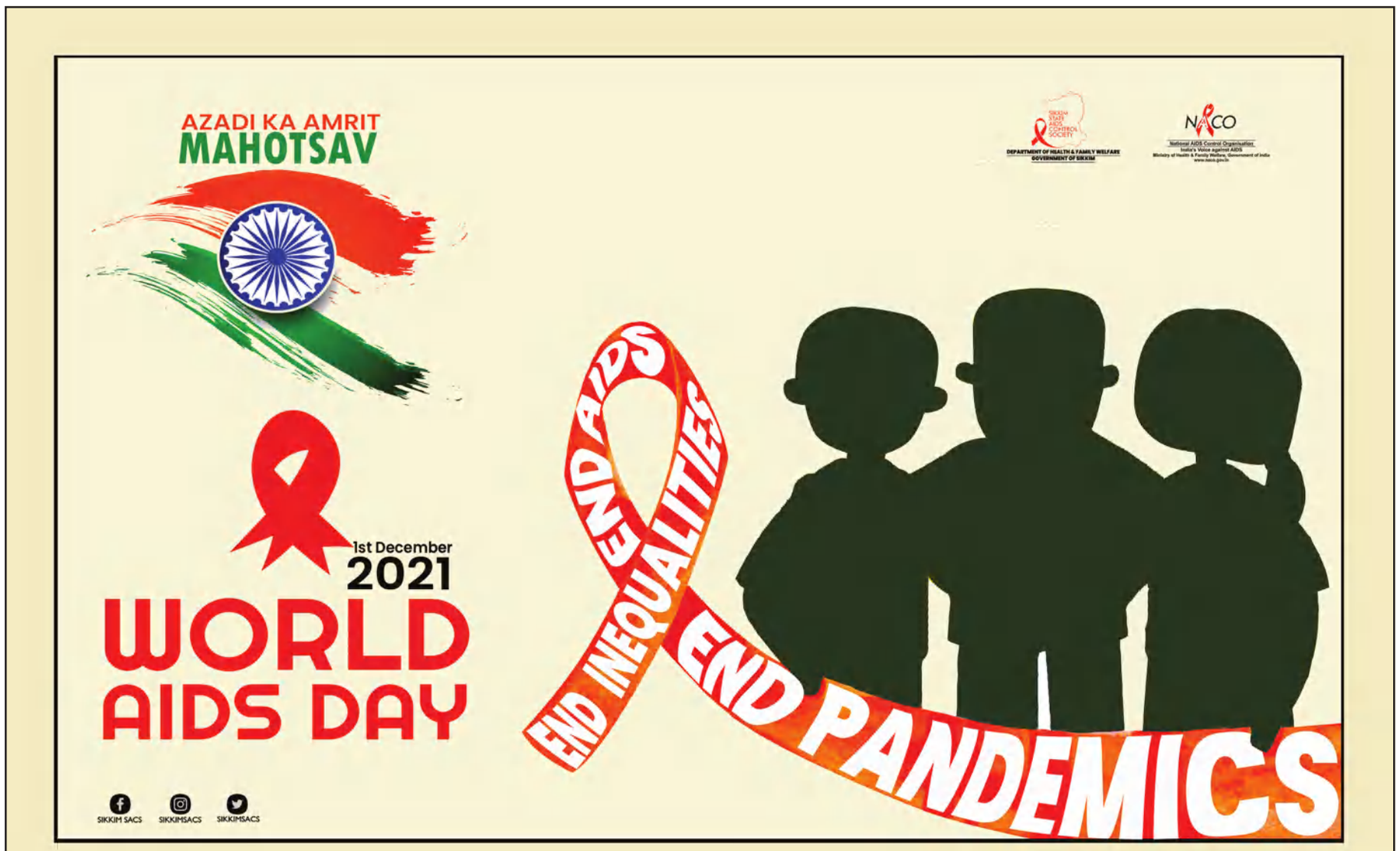

R.O. No.: 175/IPR/Pub/Dis/21-22, DT.: 24.11.2021

कोरोना के नए वेरिएंट से सतर्क यूपी में बढ़ेगी कोविड टीकाकरण की रफ्तार

लखनऊ, 30 नवम्बर (एजेन्सी)। दक्षिण अफ्रीका समेत कुछ अन्य देशों में कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमित मरीजों मिलने से सतर्क उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कोविड टीकाकरण की रफ्तार और तेज करने के निर्देश दिए हैं। कोविड टीकाकरण के मामले में देश भर में अव्वल घनी आबादी वाले उत्तर प्रदेश में चार करोड़ 95 लाख से अधिक लोगों ने टीके की दोनों खुराक प्राप्त कर ली है।

सीएम योगी ने मंगलवार को कहा कि विश्व के अनेक देशों में नए वेरिएंट के संक्रमित मिलने की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में हमें बहुत सतर्कता-सावधानी की जरूरत है। दूसरे देशों और प्रदेशों से उत्तर प्रदेश आ रहे हर व्यक्ति की जांच जरूर की जाए। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है, बिना किसी की जांच किए उसे बाहर न आने दिया जाए। केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइंस को प्रभावी रूप से लागू किया जाए।

कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर शासन की ओर से जीनोम सिक्वेंसिंग की व्यवस्था करने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लखनऊ के केजीएमयू, पीजीआई, गोरखपुर, झांसी, मेरठ में जल्द से जल्द जीनोम सिक्वेंसिंग की व्यवस्था की जाए। नगर विकास और ग्राम्य विकास विभाग प्रदेश में स्वच्छता और सेनिटाइजेशन की कार्यवाही को तेज करें। प्रदेश में निगरानी समितियों को सक्रिय करें, ताकि कोविड से संक्रमित व्यक्तियों की समय से पहचान हो जाए और उनका समय पर इलाज हो सके।

अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने बताया कि प्रदेश में चार करोड़ 95 लाख से अधिक लोगों को टीके की दोनों डोज देकर कोविड का सुरक्षा कवर प्रदान कर दिया गया है। 11 करोड़ 16 लाख लोगों ने टीके की पहली डोज प्राप्त कर ली है। यह संख्या टीकाकरण के लिए पात्र प्रदेश की कुल आबादी की लगभग 75.71 फीसदी से अधिक है। इस प्रकार प्रदेश में अब तक 16 करोड़ 11 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन डोज लगाए जा चुके हैं। कोविड टेस्टिंग और टीकाकरण में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है।

नवनीत सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कोविड टीकाकरण को और तेज करने के लिए ठोस प्रयास करने के निर्देश दिये है। प्रदेश में घर-घर जाकर सर्वेक्षण किया जायेगा जबकि अब तक पहली डोज न पाने लेने वालों की अलग सूची तैयार की जायेगी वहीं जिनका दूसरा डोज ओवरड्यू हो गया हो उनकी पृथक सूची बनाई जाएगी। दिव्यांग, अक्षम, निराश्रित, वृद्ध जनों से संपर्क कर उनका टीकाकरण किया जाएगा। इसके लिए सीएमओ स्तर से ग्राम प्रधानों, पार्षदों का सहयोग लिया जाएगा। पिछले 24 घंटों में हुई एक लाख 26 हजार 55 सैम्पल की जांच में कुल 12 संक्रमितों की पुष्टि हुई। इसी अवधि में नौ संक्रमित कोरोना मुक्त भी हुए। आज प्रदेश में कुल एक्टिव कोविड केस की संख्या 89 है। कोविड पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के लिए सावधानी और सतर्कता जरूरी है।

बीजेपी का तंज

सोनिया गांधी का समय पूरा, अब ममता बनर्जी चाहती हैं विपक्ष का नेतृत्व करना

कोलकाता, 30 नवम्बर (एजेन्सी)। टीएमसी प्रमुख व बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के केंद्रीय राजनीति में सक्रिय होने को देखते हुए भाजपा ने कांग्रेस पर तंज किया है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व बंगाल के नेता दिलीप घोष ने कांग्रेस-तृणमूल के बीच बढ़ते फासले को लेकर कहा कि सोनिया गांधी का समय पूरा हो चुका है। अब ममता बनर्जी विपक्ष का नेतृत्व करना चाहती हैं।

घोष ने यह भी कहा कि विपक्ष का ये नाटक काफी पुराना है। विपक्ष की हर पार्टी चाहती है कि वह नेतृत्व करे। ममता बनर्जी भी विपक्ष की नेता बनना चाहती हैं।

दरअसल ममता बनर्जी बीते कुछ महीनों से दिल्ली से लेकर कोलकाता तक राष्ट्रीय राजनीति के मुद्दे पर सक्रिय हैं। मंगलवार से वह तीन दिनी मुंबई दौरे पर हैं। जहां वह शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, राकांपा प्रमुख शरद पवार व अन्य नेताओं से मिलकर भाजपा के खिलाफ विपक्ष को लामबंद करने का प्रयास करेंगी। हालांकि अभी ममता ने कांग्रेस से दूरी बनाए रखी है।

सोमवार से शुरू हुए शीतकालीन सत्र को लेकर भी कांग्रेस और टीएमसी के बीच खींचतान खुलकर सामने आई है। इससे पहले भी दोनों के बीच दूरियां काफी बढ़ी हुई थीं। कांग्रेस नेताओं के तेजी से टीएमसी के दामन थामने से दोनों के रिश्तों में खटास आई है।

ऐसे में टीएमसी ने तो संसद सत्र को लेकर कांग्रेस द्वारा बुलाई गई बैठक में हिस्सा लिया और न ही केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियों के साथ शामिल हुई। कांग्रेस ने यह बैठक शीतकालीन सत्र को लेकर विपक्ष की साझा रणनीति बनाने के लिए बुलाई थी।

उधर, कांग्रेस की तरफ से टीएमसी पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। पिछले दिनों कांग्रेस ने कहा था कि टीएमसी किसानों के मुद्दे पर मिली जीत का श्रेय लेने की कोशिश कर रही है जबकि वह इस लड़ाई में कहीं थी ही नहीं। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि टीएमसी और भाजपा ने अंदरूनी सांठगांठ कर रखी है। टीएमसी डबल गेम खेल रही है।

इसी साल अगस्त में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और कांग्रेसी की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच में मुलाकात हुई थी। तब दोनों की ही तरफ से बातचीत सकारात्मक दिशा में बढ़ने का संकेत मिला था। तब ममता बनर्जी ने कहा था कि केंद्र सरकार के खिलाफ सभी विपक्षी दलों को एकजुट होना चाहिए, लेकिन उसके बाद कांग्रेस टीएमसी करीब आने की बजाए दूर होते जा रहे हैं।

ममता को झटका, नवाब मलिक बोले- कांग्रेस के बिना विपक्षी मोर्चा संभव नहीं

नई दिल्ली, 30 नवम्बर (एजेन्सी)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी दो दिन के दौरे पर मंगलवार को मुंबई पहुंची। ममता बनर्जी के इस दौरे के बाद से एक बार फिर से बीजेपी के खिलाफ तीसरे मोर्चे की चर्चा तेज हो गई है। मुंबई पहुंची ममता बनर्जी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार से बुधवार को मुलाकात करेंगी। शरद पवार से मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा शुरू हो गई है कि ममता बनर्जी कांग्रेस से दूरी बनाते हुए क्षेत्रीय दलों को एकजुट करने का प्रयास कर रही हैं।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक ने मंगलवार को पुष्टि की कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार दोपहर को राकांपा प्रमुख शरद पवार से मुलाकात करेंगी। रिपोर्ट के मुताबिक मलिक ने कहा 'ममता दीदी महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और कल दोपहर 3 बजे पवार साहल से मुलाकात करेंगी। हालांकि मलिक ने ममता के इस यात्रा को सद्भावना यात्रा करार देते हुए कहा कि एनसीपी प्रमुख से मुलाकात के बाद वह मीडिया से बात करेंगी और मीटिंग के बारे में जानकारी साझा करेंगी।'

एक सवाल के जवाब में मलिक ने कहा कि हर पार्टी को अपना आधार बढ़ाने का प्रयास करने का पूरा अधिकार है, लेकिन कांग्रेस को बाहर रखकर बीजेपी के विरोधियों को एकजुट करना असंभव है। मलिक ने कहा 'बंगाल के बाहर टीएमसी का विस्तार हो रहा है और यह हर राजनीतिक दल का अधिकार है। हालांकि, हम मानते हैं कि कांग्रेस को छोड़कर एक संयुक्त विपक्षी मोर्चा संभव नहीं है। पवार साहब भी कई बार इसे स्पष्ट कर चुके हैं।'

वहीं, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर एक सवाल के जवाब में, मलिक ने कहा कि अधिकांश राजनीति से प्रेरित थे और सच्चाई जल्द ही सामने आएगी। बता दें कि मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में गिरफ्तारी के बाद से नवाब मलिक लगातार सुर्खियों में रहे हैं। खासकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ वो लगातार एक के बाद एक बड़े दावे किए हैं।

आजादी के बाद से कभी नहीं हुई एससी-एसटी के अलावा जातिगत गणना, नित्यानंद राय की दो टूक

नई दिल्ली, 30 नवम्बर (एजेन्सी)। विपक्षी दलों व केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए के भी कुछ घटक दलों द्वारा लगातार की जा रही देश में जातिगत जनगणना की मांग के बीच केंद्र सरकार ने लोकसभा में इस पर खरी-खरी कही। गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में कहा कि आजादी के बाद से भारत सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य जाति-वार आबादी की गणना कभी नहीं की है।

मंत्री राय ने कहा कि जनगणना कार्यक्रम केंद्रीय मंत्रालयों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ विचार विमर्श के बाद तैयारकिया गया है। राय के बयान से स्पष्ट है कि केंद्र जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में नहीं है। विपक्षी दलों के अलावा बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन की घटक नीतीश कुमार नीत जेडीयू भी इसकी मांग कर रहा है।

गृह राज्यमंत्री ने कहा कि जनगणना-2021 कराने की सरकार की मंशा 28 मार्च, 2019 को राजपत्र में इसे अधिसूचित करने से प्रकट हो गई थी, लेकिन कोविड-19 के महामारी के कारण जनगणना कार्यों को स्थगित कर दिया गया है।

लोकसभा में पूछा गया था कि क्या सरकार ने 2021-22 में जाति आधारित जनगणना कराने पर विचार किया है? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री राय ने जवाब में कहा कि जिन जातियों और जनजातियों को विशेष रूप से संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 के अनुसार अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के रूप में अधिसूचित किया गया है, उनकी गणना की जाती है।

उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से जनगणना में अजा-जजा के अलावा अन्य जाति के आधार पर आबादी की गणना नहीं की है। पिछले कई दिनों से देश के कई राजनीतिक दल जातिवार जनगणना की मांग कर रहे हैं। इसमें आरजेडी, जेडीयू और सपा समेत कई राजनीतिक पार्टियां शामिल हैं। केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना कराने की विपक्ष की मांग के मंजूर करने के पक्ष में नहीं है।

तीन दिन में दूसरी बार भाजपा ने सपा-बसपा को दिया झटका, पूर्व विधायक जगपाल सिंह समेत कई नेता पार्टी में शामिल

लखनऊ, 30 नवम्बर (एजेन्सी)। यूपी विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे नेताओं का पाला बदल तेज हो रहा है। भाजपा ने मंगलवार को एक बार फिर सपा-बसपा को झटका देते हुए कई नेताओं को पार्टी में शामिल किया है। इनमें सबसे बड़ा नाम चार बार के पूर्व विधायक बसपा नेता जगपाल सिंह का नाम शामिल है। भाजपा ने पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक के कई नेताओं को पार्टी में शामिल किया है। पूर्वांचल के बलिया, मऊ, गाजीपुर से लगभग एक दर्जन नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ली है। आठ बीएसपी नेताओं ने भाजपा का दामन थामा है। पूर्व विधायक जगपाल सिंह के अलावा बलिया के बसपा नेता छट्टू प्रसाद, अजय कुमार, देवरिया के अमरेश कुमार सिंह, सपा नेता राना दिनेश प्रताप सिंह ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है।

इससे पहले रविवार को सपा सरकार में मंत्री रहे गाजीपुर के पूर्व मंत्री विजय मिश्रा सहित कई नेताओं ने भाजपा का दामन थामा था। जो लोग भाजपा में शामिल हुए उनमें पूर्व मंत्री जय नारायण तिवारी सुल्तानपुर सपा से, मनोज दिवाकर बसपा नेता कानपुर से, जगदेव बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष, अशोक कुमार सिंह पूर्व आईएएस, राम शिरोमणि शुक्ला कांग्रेस के पूर्व विधायक, धर्मेंद्र पांडेय उन्नाव से बसपा नेता, मदन गौतम पूर्व विधायक ओरैया से बसपा से, कुंवर अभिमन्यु सिंह अयोध्या से समाजसेवी शामिल हुए थे।

बसपा का गढ़ कहे जाने वाले जनपद सहारनपुर में बसपा को झटके पर झटके लग रहे हैं। हरौड़ा (वर्तमान में सहारनपुर देहात) से तीन बार विधायक चुने गए जगपाल सिंह भाजपा में शामिल हो गए। हरौड़ा विधानसभा सीट से वर्ष 1997 का चुनाव जीतकर मायावती गठबंधन की सरकार में मुख्यमंत्री बनी थीं। सरकार गिर जाने के कारण जब मायावती ने इस सीट से इस्तीफा दिया तो उनके प्रतिनिधि के रूप में जगपाल सिंह पहली बार बसपा के टिकट पर उप चुनाव लड़कर विधायक निर्वाचित हुए थे। वर्ष 2002 में हुए चुनाव में भी इस सीट से बसपा सुप्रीमों मायावती चुनाव लड़ी और प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी।

मगर बाद में मायावती द्वारा इस्तीफा दिये जाने के कारण इस सीट पर वर्ष 2003 में हुए उपचुनाव में जगपाल सिंह फिर चुनाव लड़े मगर वह चुनाव हार गए थे। इसके बाद वर्ष 2007 और वर्ष 2012 में सामान्य हुई इस सीट पर लगातार जगपाल सिंह विधायक चुने गए। वर्ष 2017 में हुए चुनाव में जगपाल सिंह मामूली अंतर से कांग्रेस के मसूद अख्तर से चुनाव हार गए। इसके बाद से जिले में बसपा में लगातार उथल-पुथल मची है और एक-एक कर बसपा के कई बड़े नेता पार्टी छोड़ दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं।

कोर्ट के आदेश पर यूपी में मार्क जुकरबर्ग के खिलाफ मुकदमा दर्ज

कन्नौज, 30 नवम्बर (एजेन्सी)। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कन्नौज के ठठिया थाना में रिपोर्ट दर्ज है। कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई रिपोर्ट में 49 और लोगों को भी वादी बनाया गया है। यह रिपोर्ट फेसबुक पर बुआ-बबुआ के नाम से पेज बनाकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की छवि खराब करने के आरोप में दर्ज हुई है।

ठठिया थाना क्षेत्र के सराहटी गांव के रहने वाले अमित कुमार की शिकायत के बाद यह रिपोर्ट दर्ज की गई है। अमित कुमार ने बताया है कि वह समाजवादी विचारधारा से प्रभावित है। समाजवादी पार्टी का समर्थक है। सपा मुखिया अखिलेश यादव में उसकी सियासी आस्था है। उसकी शिकायत है कि फेसबुक पर बुआ-बबुआ के नाम से एक पेज बना हुआ है। उस पेज पर आए दिन सपा मुखिया के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की जाती है। उनका कार्टून बनाकर उनकी छवि खराब की जाती है। उनके साथ ही कई और नेताओं को भी उसमें गलत बताया जाता है। आपत्तिजनक वीडिया बनाकर पोस्ट किया जाता है। फिर उस पर अशोभनीय टिप्पणी की जाती है। उसका कहना है कि उसने पहले ठठिया थाना में शिकायत की, लेकिन संज्ञान नहीं लिया गया। ऐसे में उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश पर ठठिया थाना में फेसबुक संस्थापक व पेज एडमिन सहित 49 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है।

इस मामले में एसपी प्रशांत वर्मा ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर फेसबुक फाउंडर, पेज एडमिन व उसे लाइक, कमेंट व शेयर करने वाले 49 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।

साइबर टीम की मदद से पहले तो कंटेंट की जांच की जाएगी। यह देखा जाएगा कि आपत्तीजनक मामला क्या है। उसमें कोई आपराधिक एंगल सामने आता है तो ही कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई जाएगी।

परमबीर सिंह ने सीआईडी कार्यालय में छह घंटे तक बयान दर्ज कराया

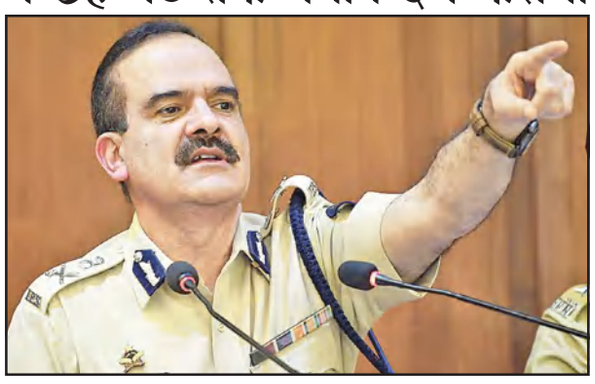

मुंबई, 30 नवम्बर (एजेन्सी)। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख परमबीर सिंह ने रंगदारी के एक मामले में सोमवार को नवी मुंबई स्थित सीआईडी के कार्यालय में करीब 6 घंटे तक अपना बयान दर्ज कराया। इसके साथ ही तीन कांस्टेबलों और एक अधिकारी के बयान दर्ज किए, जिन्होंने एपीआई सचिन वाजे को न्यायमूर्ति चांदीवाल आयोग के समक्ष सुनवाई के लिए एस्कॉर्ट किया था।परमबीर सिंह को मंगलवार को फिर से एजेंसी के सामने पेश होने को कहा गया है।

लंबे समय के बाद परमबीर सिंह और सचिन वाजे ने एक साथ आमने-सामने बात की। मुंबई पुलिस ने नवी मुंबई में अपने समकक्षों से यह भी जांच करने के लिए कहा कि कैसे दोनों एक-दूसरे से बात करने में कामयाब रहे और वह भी इतने लंबे समय तक। सूत्रों ने कहा कि सिंह और वेज़ एक दूसरे के साथ 30 मिनट से अधिक समय तक बात कर रहे थे, औ

राज्य के पूर्व गृह मंत्री और राकांपा नेता अनिल देशमुख के वकील द्वारा न्यायमूर्ति चांदीवाल आयोग के समक्ष इस पर आपत्ति जताई गई थी। आयोग के परिसर में एक अन्य कमरे में सिंह और वाजे के एक साथ बैठने पर देशमुख के वकील द्वारा आयोग पर आपत्ति जताए जाने के बाद, न्यायमूर्ति चांदीवाल (सेवानिवृत्त) ने शुरू में कहा, इसे कैसे रोका जा सकता है?

बाद में उन्होंने वाजे से कहा कि ऐसी स्थिति से बचने के लिए इस कमरे में बैठना बेहतर है (जहां आयोग की कार्यवाही हो रही थी। एक सदस्यीय आयोग का गठन राज्य सरकार ने सिंह द्वारा मुंबई पुलिस आयुक्त के पद से हटाए जाने के बाद देशमुख के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए किया था।

सचिन वाजे मामले के संबंध में जिरह के लिए आयोग के समक्ष पेश हो रहे हैं। देशमुख के वकील ने दिन में कहा था, परमबीर सिंह और सचिन वाजे पिछले एक घंटे से एक साथ बैठे हैं। वह गवाह सचिन को प्रभावित कर सकते हैं। सचिन वाजे और सिंह दोनों गोरेगांव में दर्ज एक जबरन वसूली मामले में सह-आरोपी हैं, पूर्व भी एंटीलिया बम डराने-मनसुख हिरन हत्या मामले के सिलसिले में जेल में है।

वहीं, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख आज मुंबई में चांदीवाल आयोग के समक्ष पेश हुए। सरकार ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह के देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए चांदीवाल आयोग का गठन किया था।

किसान, नौजवान व गरीब महंगाई की मार से सभी टूट गए : अखिलेश

लखनऊ, 30 नवम्बर (एजेन्सी)। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा ने जनता को बुरी तरह निराश किया है। उसकी नीतियों और कार्यप्रणाली से उत्तर प्रदेश की जनता असंतुष्ट है। किसान, नौजवान, गरीब महंगाई की मार से टूट गए हैं। इसलिए जनता अब भाजपा से मुक्ति चाहती है। उसको भरोसा है कि समाजवादी सरकार बनने पर ही भला होगा।

अखिलेश ने मंगलवार को पार्टी कार्यालय लखनऊ में डॉ. राममनोहर लोहिया सभागार में एकत्र कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने देश की अर्थव्यवस्था को तहस-नहस करने के साथ नोटबंदी और जीएसटी से व्यापार और काम धंधा चौपट कर दिया है। विकास अवरुद्ध है। लोगों को बहकाने के लिए भाजपा सरकार लोकार्पण और शिलान्यास का नाटक कर रही है।

उन्होंने कहा कि सच तो यह है कि भाजपा ने अब तक एक ही काम किया है वह है समाजवादी पार्टी के विरुद्ध साजिशें रचने का। भाजपा का काम झूठे आरोपों का प्रचार-प्रसार करना है। राजनीति को अभद्र भाषा और असंगत कार्य व्यवहार से भाजपा ने बुरी तरह प्रदूषित किया है।

भाजपा को लोकलाज के विरुद्ध आचरण करने में जरा भी संकोच नहीं। भाजपा राज में अन्नदाता किसान और नौजवानों की उपेक्षा हुई है। हक के लिए लड़ रहे किसानों को भाजपा ने लांछित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। होहल्ले के बावजूद निवेश नहीं आया। नौकरियां मिलने के बजाय छूट रही हैं। जनता ने वर्ष 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी।

यूपी की मिलों में अब चीनी कम, एथेनॉल ज्यादा बनेगा

लखनऊ, 30 नवम्बर (एजेन्सी)। उत्तर प्रदेश में अब चीनी मिलों को चीनी नहीं बल्कि एथेनॉल ज्यादा रास आ रहा है। चालू पेराई सत्र में गोंडा में मेजापुर चीनी मिल में गन्ने के रस से सीधे एथेनॉल बनाने का प्लांट चालू होने वाला है। बलरामपुर चीनी मिल समूह का यह प्लांट एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है। इस मिल में करीब 300 करोड़ रुपये का चीनी का उत्पादन होता था।

इसके अलावा कई निजी व सरकारी क्षेत्र की मिलों ने हैवी शीरे से चीनी के बजाए एथेनॉल ही बनाने की ठानी है। उत्तर प्रदेश चीनी निगम की गोरखपुर स्थित पिपराइच चीनी मिल में भी आने वाले दिनों में सीधे गन्ने के रस से एथेनॉल ही बनाया जाएगा। गन्ना विकास व चीनी उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय आर भूसरेड्डी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले पेराई सत्र के मुकाबले इस बार करीब 12 प्रतिशत चीनी कम बनेगी। इस तरह से इस बार 120 लाख मीलियन टन के वार्षिक उत्पादन के मुकाबले करीब 105 लाख मीलियन टन चीनी का उत्पादन होने के आसार हैं जबकि इस बार एथेनॉल का 160 करोड़ लीटर उत्पादन होने का लक्ष्य तय किया गया है।

भूसरेड्डी ने बताया कि यूपी सर्वाधिक एथेनॉल उत्पादन करने वाला राज्य है। यहां एथेनॉल बने का करीब साठ फीसदी हिस्सा अपने राज्य में ही पेट्रोल में मिलाकर हरित ईंधन के तौर पर प्रयुक्त किया जाता है। अभी पेट्रोल में करीब 10 प्रतिशत एथेनॉल मिलाया जाता है, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बढ़ाकर 14 प्रतिशत किए जाने की मांग की है।

उन्होंने बताया कि मिलों में चीनी उत्पादन घटाकर एथानाल का उत्पादन बढ़ाए जाने से गन्ना किसानों को उनके गन्ने का मूल्य भुगतान करने में भी आसानी होगी क्योंकि बाजार में चीनी के बजाए एथेनॉल से ज्यादा जल्दी और अच्छे दाम मिलों को मिलते हैं। भूसरेड्डी के अनुसार प्रदेश में इस बार अब तक 124 में से 100 मिलें पेराई शुरू कर चुकी हैं।

हमेशा के लिए माल्या का इंजतार नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 30 नवम्बर (एजेन्सी)। विजय माल्या के खिलाफ अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहम घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विजय माल्या को जिस मामले में भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को दोषी ठहराया गया है उस पर 18 जनवरी 2022 को अंतिम सुनवाई की जाएगी। माल्या को 2017 में अवमानना का दोषी ठहराया गया था।

न्यायधीश यूयू ललित, एसआर भट और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत ने काफी लंबा इंतजार किया है। हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। पीठ ने कहा कि विजय माल्या के खिलाफ अवमानना के इस मामले का किसी न किसी स्तर पर निपटारा करना ही होगा। अब इस प्रक्रिया को समाप्त हो जाना चाहिए।

अदालत ने कहा कि हम हमेशा के लिए विजय माल्या का इंतजार नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने माल्या को पेश होने का निर्देश दिया था, लेकिन वह हाजिर नहीं हुआ था। इससे पहले कोर्ट ने इस केस में 2017 के फैसले पर माल्या की पुनर्विचार की याचिका भी खारिज कर दी थी।

इस मामले में माल्या को न्यायिक आदेशों का उल्लंघन करके बच्चों को चार करोड़ अमेरिकी डॉलर भेजने के लिए अवमानना का दोषी ठहराया गया था। वहीं, 18 जनवरी को केंद्र ने अदालत को बताया था कि कुछ कानूनी मुद्दों के कारण माल्या के प्रत्यर्पण में देर हो रही है।

शीर्ष अदालत ने मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता से न्याय मित्र के रूप में सहायता करने का अनुरोध किया। साथ ही अदालत ने कहा कि विजय माल्या अभिवेदन को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर वह मौजूद नहीं है, तो उसकी ओर से वकील बहस कर सकता है।

बता दें कि विजय माल्या मार्च 2016 से ब्रिटेन में रह रहा है। वह अपनी बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस से जुड़े 9000 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक कर्ज धोखाधड़ी के मामले में आरोपियों में से एक है। फिलहाल प्रत्यर्पण के एक मामले में जमानत पर बाहर चल रहा है।

राहुल गांधी के ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने साधा निशाना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर (एजेन्सी)। राहुल गांधी के ट्वीट पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री और राज्य सभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा कि सांसदों को सदन में जनता की बात उठाने का पूरा अधिकार है लेकिन उसका एक तरीका होता है, नियम होता है।

राहुल गांधी से सवाल पूछते हुए गोयल ने कहा कि उन्हें अपने अगले ट्वीट में देश को यह बताना चाहिए कि क्या इन 12 सांसदों ने जिस तरह का व्यवहार सदन में किया, उसे वो सही मानते हैं ?

राज्य सभा सभापति पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा लगाए गए आरोपों की भी कड़ी निंदा करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सदन और सभापति का अपमान इन सांसदों द्वारा किया गया था और इन सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करने का पूरा अधिकार था।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सदन और सभापति का अपमान करने वाले इन सांसदों को माफी मांग लेनी चाहिए, ताकि अच्छे वातावरण में लोक सभा और राज्य सभा दोनों सदन चल सके और सदन में कोरोना के बढ़ रहे खतरे (नए वैरिएंट) और देश की अन्य समस्याओं पर सही तरीके से चर्चा हो सके।

विरोधी दलों पर तीखा हमला जारी रखते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि सभापति लगातार विपक्ष से सदन चलने देने की अपील करते रहे, लेकिन मानसून सत्र में विपक्ष पहले दिन से ही सदन नहीं चलने देने पर आमादा था। पूरा देश उनकी मंशा को समझ और देख रहा था। विरोधी दल पहले दिन से ही लगातार सदन और चेयर का अपमान कर रहे थे और मानसून सत्र के आखिरी दिन 11 अगस्त को उन्होंने जो घिनौनी हरकत की उसका सच उन्ही के द्वारा किए गए वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए सारे देश ने देखा। इसलिए उसके बाद आए पहले सत्र के पहले दिन ही सरकार ने सदन, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की गरिमा बनाए रखने के लिए इन 12 सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध सदन से किया।

टेबल पर चढ़ने वाले विरोधी दलों के अन्य सांसदों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के विपक्षी नेताओं के बयान पर बोलते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि अगर ऐसा है तो ये दल उन सांसदों के निलंबन का प्रस्ताव लेकर राज्य सभा में आ जाए, हम उनका समर्थन करेंगे।

जिला स्तरीय भाषण .....

विकास, सबका विश्वास के नारे के साथ देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण के विषयों का एक विस्तृत संभाषण रखा गया था। प्रतियोगिता के निर्णायक पूरण छेत्री, नमो दीक्षित, जेबा अंसारी, बिमल गुरुंग, शरोन राई और राकेश प्रधान शामिल थे।

प्रतियोगिता में कुल 14 विद्यार्थियों ने भाग लिया। उल्लेखनीय है कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता में विजयी बनने वाली शेरोन राई राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में दक्षिण जिले का प्रतिनिधित्व करेंगी।

मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही यूपी सरकार : मायावती

लखनऊ, 30 नवम्बर (एजेन्सी)। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने मंगलवार को आरोप लगाया कि जातिवादी मानसिकता के कारण केंद्र सरकार जातिवार जनगणना की मांग की अनदेखी कर रही है और उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही और उनमें डर पैदा कर रही है।

मंगलवार को बसपा के लखनऊ कार्यालय में पार्टी के ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग), मुस्लिम और जाट समाज के मुख्य और मंडल सेक्टर स्तर के वरिष्ठ पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक के बाद मायावती ने जातिवार जनगणना का समर्थन करते हुए पत्रकारों से कहा कि ओबीसी समाज की जातिवार जनगणना कराने की मांग से बसपा पूरी तौर से सहमत है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा जातिवादी मानसिकता के चलते नजरअंदाज किया जा रहा है।

मायावती ने यह बैठक उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षित 86 विधानसभा सीटों में मुस्लिमों और जाट समुदाय को जोड़ने के लिए पार्टी पदाधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा के लिए बुलाई थी। उन्होंने सत्तारूढ़ भाजपा पर मुसलमानों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाते हुए कहा, ''भाजपा की प्रदेश सरकार से मुस्लिम समाज दुखी है और इनकी तरक्की बंद है। उन्होंने कहा, ''ज्यादातर फर्जी मुकदमों में फंसाकर इनका (मुसलमानों का) उत्पीड़न किया जा रहा है और नए-नए नियमों के तहत इनमें काफी दहशत पैदा की जा रही है, जो ये सब मेरी सरकार में कतई नहीं हुआ है, ये बात भी सर्वविदित है।''

मायावती ने कहा, ''लेकिन इससे भाजपा का इनके प्रति सौतेला रवैया साफ नजर आ रहा है। जबकि बसपा सरकार में इनकी तरक्की के साथ साथ इनके जान माल की पूरी हिफाजत की गई है। इनके साथ साथ जाट समाज की तरक्की का पूरा पूरा ध्यान रखा गया है।उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिलने का श्रेय बाबा साहब को देते हुए यह भी दावा किया कि आजादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की। लेकिन बसपा ने अपने अथक प्रयासों से केंद्र में वीपी सिंह की सरकार में इसे लागू करवाया और तब जाकर देश में ओबीसी वर्गों को दलितों और आदिवासियों की तरह आरक्षण की सुविधा मिली है।

मायावती ने आरोप लगाया कि केंद्र व राज्यों की जातिवादी सरकारें आये दिन नियम व कानून बनाकर इनके आरक्षण को प्रभावहीन बनाने में लगी हैं। बसपा प्रमुख ने पत्रकारों को बताया कि आज (मंगलवार को)बसपा के लखनऊ कार्यालय में पार्टी के ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग), मुस्लिम और जाट समाज के मुख्य और मंडल सेक्टर स्तर के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई जिनको प्रदेश की आरक्षित विधानसभा सीटों पर अपने-अपने समाज के लोगों को बसपा में जोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

उन्होंने कहा कि इन समुदायों के लोग सामान्य सीटों पर भी काम कर रहे हैं और उनकी बैठक पहले हो चुकी है। मायावती ने वादा किया कि अगर बसपा सत्ता में आती है तो उनकी सरकार मुसलमानों के अलावा, जाट और ओबीसी समुदायों की प्रगति, कल्याण और सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगी।

एक सवाल के जवाब में मायावती ने कहा कि बसपा अकेले अपने बूते पर 403 सीटों पर पूरी दमदारी से चुनाव लड़ेगी और 2007 की तरह पूर्ण बहुमत से हमारी पार्टी सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा कि किसी से समझौते का कोई सवाल ही नहीं है।

राज्यसभा सभापति ने 12 सांसदों का निलंबन रद्द करने का अनुरोध ठुकराया

नई दिल्ली, 30 नवम्बर (एजेन्सी)। राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने मंगलवार को 12 सांसदों के निलंबन को रद्द करने की विपक्ष की अपील को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा, 'मैं विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की 12 सांसदों के निलंबन को रद्द करने की अपील पर विचार नहीं कर रहा हूं क्योंकि निलंबित सांसदों ने माफी नहीं मांगी है, वे अपने व्यवहार को सही ठहरा रहे हैं।' इस पर विपक्षी सदस्यों ने वॉक आउट कर दिया।

खड़गे ने नियम 256 के तहत यह मुद्दा उठाते हुए कहा था कि निलंबन नियमों के विपरीत है।

विपक्ष के नेता ने कहा, 'सदस्यों को पिछले सत्र में हुए आचरण और सदन के नियमों के खिलाफ होने के कारण निलंबित कर दिया गया है।' उन्होंने कहा कि माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता।

जवाब में, सभापति ने कहा कि सदन ने एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और घटना के दिन, सभापति द्वारा सांसदों को नामित किया गया था।

मंगलवार की सुबह, टीएमसी को छोड़कर, विपक्षी दल इस मामले पर रणनीति बनाने के लिए खड़गे के कार्यालय में इकट्ठे हुए और सभापति से मिले, लेकिन निराशा हाथ लगी।

अपने कृत्य को सही ठहराते हुए, टीएमसी के डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि सदस्यों को मानसून सत्र में इस तरह के व्यवहार का सहारा लेने के लिए मजबूर किया गया था क्योंकि कुछ मुद्दों को बार-बार अनुरोध के बावजूद चर्चा के लिए नहीं लाया जा रहा था। उन्होंने कहा, '12 विपक्षी सांसदों को नहीं बल्कि ट्रिजरी के 80 सांसदों को निलंबित किया जाना चाहिए।'

उच्च सदन ने सोमवार को 11 अगस्त को मानसून सत्र के दौरान सदन में हंगामा करने पर 12 सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया था।

निलंबित सांसद कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, भाकपा, माकपा और शिवसेना से हैं।

निलंबित सदस्य सैयद नसीर हुसैन, अखिलेश प्रसाद सिंह, फूलो देवी नेताम, छाया वर्मा, रिपुन बोरा और कांग्रेस के राजमणि पटेल, प्रियंका चतुर्वेदी, शिवसेना के अनिल देसाई, माकपा के एलाराम करीम, के बिनॉय विश्वम भाकपा, डोला सेन और तृणमूल की शांता छेत्री है।

राज्यों को ओमिक्रॉन खतरे से बचने के लिए केंद्र ने दिए निर्देश

नई दिल्ली, 30 नवम्बर (एजेन्सी)। केंद्र ने मंगलवार को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को आईसीयू, ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर आदि की उपलब्धता जैसे स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की तैयारी सुनिश्चित करने और ग्रामीण क्षेत्रों और बाल चिकित्सा के लिए ईसीआरपी-2 को लागू करने की सलाह दी।

केंद्र ने ओमिक्रॉन संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच लॉजिस्टिक्स, दवाओं, ऑक्सीजन सिलेंडरों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ स्वीकृत पीएसए संयंत्रों के शीघ्र कार्यान्वयन पर जोर दिया।

ओमिक्रॉन वेरिएंट की रिपोर्ट के बीच सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया उपायों और तैयारियों पर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ एक वर्चुअल बैठक में, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को सलाह दी कि वे देश में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों पर कड़ी निगरानी रखें।

राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की प्रभावी निगरानी करने की सलाह दी गई है। राज्यों को आरटी-पीसीआर अनुपात बनाए रखते हुए प्रत्येक जिले में पर्याप्त परीक्षण सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। उन्हें उन क्षेत्रों की निगरानी जारी रखनी होगी जहां हाल ही में पॉजिटिव मामलों का समूह सामने आया है। होम आइसोलेशन के मामलों की प्रभावी और नियमित निगरानी नियमित रूप से की जाएगी, जिसमें 'जोखिम वाले' देशों के यात्रियों के घरों का फिजिकल दौरा किया जाएगा।

सभी राज्यों को बीओआई, एपीएचओ, पीएचओ और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करने की सलाह दी गई है ताकि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए मध्यरात्रि से लागू होने वाले नए दिशानिर्देश को सुचारू रूप से लागू किया जा सके।

NAGALAND STATE LOTTERIES

Draw Time: 01:00 PM

DEAR TEESTA MORNING

Draw No:53 DrawDate on:30/11/21

1st Prize ₹1 Crore/- 67K 43293

Cons. Prize Rs.1000/- 43293 (REMAINING ALL SERIALS)

2nd Prize ₹9000/-

04708 09667 18014 28869 43530 46706 73093 79633 91485 94077

3rd Prize ₹450/-

0291 1821 3888 5090 5416 5476 5588 6996 7808 8631

4th Prize ₹250/-

0683 0694 0760 1890 3033 3708 5447 6280 8288 9856

5th Prize ₹120/-

0252 0338 0433 0457 0478 0524 0537 0759 1052 1248
1305 1359 1563 1889 1907 1994 2097 2156 2158 2174
2324 2399 2424 2434 2570 2626 2652 2653 2674 2730
3240 3417 3479 3559 3628 3724 3732 4208 4459 4733
4762 4804 4903 4934 5008 5062 5086 5407 5500 5642
5782 5865 5998 6063 6229 6261 6307 6384 6480 6950
7077 7124 7166 7208 7220 7288 7398 7652 7828 7841
7857 7862 7895 7908 7931 7952 7973 7976 8125 8204
8220 8295 8416 8467 8552 8606 8642 8659 8922 8941
8944 8946 9045 9228 9293 9406 9452 9504 9921 9988

KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

NAGALAND STATE LOTTERIES

Draw Time: 08:00 PM

DEAR PARROT EVENING

Draw No:153 DrawDate on:30/11/21

1st Prize ₹1 Crore/- 63L 75408

Cons. Prize Rs.1000/- 75408 (REMAINING ALL SERIALS)

2nd Prize ₹9000/-

03869 13128 15354 26935 32549 43477 90248 92308 92310 94947

3rd Prize ₹450/-

0694 1730 2271 2770 4543 4590 5542 6601 8666 9897

4th Prize ₹250/-

0110 0355 0750 0795 1108 1508 2825 6842 9108 9683

5th Prize ₹120/-

0003 0211 0224 0414 0433 0734 0772 1049 1083 1089
1107 1141 1319 1353 1366 1691 1792 1802 1807 1896
2197 2273 2304 2600 2677 2986 3014 3030 3207 3225
3285 3324 3337 3509 3615 3805 3933 3947 3984 4000
4053 4195 4234 4256 4306 4785 4820 4916 5022 5124
5204 5307 5475 5650 5681 5743 5807 5813 5331 5870
5978 6053 6060 6140 6304 6316 6678 6834 6884 6903
6925 7117 7209 7261 7530 7589 7650 7701 7752 7770
8032 8139 8296 8349 8439 8465 8532 8589 8678 8899
8900 9341 9380 9425 9500 9779 9841 9852 9957 9962

KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

NAGALAND STATE LOTTERIES

Draw Time: 06:00 PM

DEAR MOON TUESDAY

Draw No:53 DrawDate on:30/11/21

1st Prize ₹1 Crore/- 79D 49437

Cons. Prize Rs.1000/- 49437 (REMAINING ALL SERIALS)

2nd Prize ₹9000/-

10731 24268 28162 41329 45449 76085 78949 80003 83867 92189

3rd Prize ₹450/-

1098 1377 1444 1605 2367 3337 3510 7021 8734 9107

4th Prize ₹250/-

2103 2292 4277 4344 5140 6146 8817 8859 9083 9975

5th Prize ₹120/-

0119 0293 0493 0505 0581 0651 0836 0854 0877 0981
1014 1108 1110 1439 1492 1567 1585 1597 1644 1649
1706 1782 1965 2088 2261 2374 2552 2561 2817 2905
3005 3037 3162 3436 3479 3659 3668 3677 4130 4162
4397 4557 4586 4643 4984 4999 5009 5095 5225 5289
5293 5318 5478 5571 5805 6060 6113 6206 6325 6350
6354 6359 6463 7065 7078 7122 7317 7370 7408 7415
7429 7511 7519 7525 7534 7588 7600 7622 7680 7681
7798 7857 7988 8109 8463 8464 8508 8690 8927 9071
9140 9157 9206 9293 9320 9378 9633 9641 9672 9974

KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

ANTHYESTHI KRIYA

The Anthyesthi Kriya of Late Januka Devi Chapagai (Dhungel) who left for heavenly abode on 25th November 2021 falls on 7th December 2021.

All relatives, family, friends and well wishers are requested to join us in offering prayers for the departed soul at our residence at Simik Lingey (Khamdong), Busty East Sikkim. We also express our gratitude to all those who stood by us during our time of bereavement.

Ganga Ram Chapagai *(husband)*
Namrata Chapagai Sharma *(daughter)*
Yog Prasad Chapagai (brother)
Narayan Dhungel (elder brother)
and all Chapagai family
Cont No: 7407183258 / 9339227097

श्रम विभाग

सिक्किम सरकार

श्रम भवन

सोकेथांग, गंगटोक - 737 102

अपील

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सभी प्रकार के असंगठित श्रमिकों जैसे निर्माण श्रमिकों, प्रवासी श्रमिकों, घरेलू श्रमिकों, खेतिहर मजदूरों, स्वरोजगार श्रमिकों, सड़क विक्रेताओं, छोटे दुकानदारों, आशा कर्मियों, आँगनबाड़ी कार्यकर्ता, मछुआरे, असंगठित बागान कर्मियों, दूधवाले और असंगठित कामगारों के अन्य उप-समूह के लिए एक पंजीकरण मॉड्यूल/ई-श्रम पोर्टल विकसित किया है।

उनके पंजीकरण के लिए पात्रता इस प्रकार है:-

- श्रमिक की आयु 16-60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- वह आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
- वह ई.पी.एफ.ओ. और ई.एस.आई.सी. का सदस्य नहीं होना चाहिए।

ई-श्रम पोर्टल का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है:-

1. देश के असंगठित क्षेत्र के कामगारों का डेटाबेस तैयार करना।
2. श्रमिकों को उनके मोबाइल नंबर और बैंक खाते के विवरण से जुड़े अपने संबंधित आधार कार्ड नंबर की मदद से पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करने के लिए सक्षम करना। यदि किसी श्रमिक के पास आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर नहीं है, तो वह निकटतम सामुदायिक सेवा केंद्र (सी.एस.सी) पर जा सकता है और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से पंजीकरण कर सकता है।
3. श्रमिकों को ई-श्रम कार्ड प्रदान किया जाएगा जिसमें 12 अंकों को विशिष्ट नंबर होगा। इस कदम के पीछे का उद्देश्य केंद्र की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण है।
4. पोर्टल जो राष्ट्र निर्माताओं का राष्ट्रीय डेटाबेस होगा, असंगठित श्रमिकों की पहचान करने में मदद करेगा।

पंजीकरण के लाभ:-

1. असंगठित श्रमिक केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों और योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।
2. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा।
3. डेटाबेस सीमान्तकृत श्रमिकों के लिए विशेष नीतियां और योजनाएं बनाने में सरकार की मदद करेगा।
4. ई-श्रम में पंजीकरण के साथ, श्रमिकों को एक वर्ष के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पी.एम.एस.बी.वाई) का लाभ मिलेगा (आकस्मिक मृत्यु और पूर्ण विकलांगता के लिए 2 लाख रुपये और आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपये)।
5. यह प्रवासी श्रमिक कार्यबल की निशानदेही करने और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने में मदद करेगा।
6. श्रमिकों को उनके कौशल विकसित करने और रोजगार के अवसर खोजने में मदद करना।
7. आपदा की स्थिति में सहायता राशि का सीधे डी.बी.टी. के माध्यम से श्रमिकों के बैंक खातों में स्थानांतरण करना।

सिक्किम में काम करने वाले सभी असंगठित श्रमिकों से अनुरोध है कि वे सामुदायिक सेवा केंद्र (सी.एस.सी. - सम्पर्क नंबर ६२९४२-५४८८५), ग्राम स्तरीय गणनाकार (वी.एल.ई.) के माध्यम से ई-श्रम पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करवाएं या ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए सिक्किम सरकार के सोकेथांग स्थित श्रम विभाग और जिला कार्यालयों में जा सकते हैं।

संयुक्त श्रम आयुक्त
श्रम विभाग
सिक्किम सरकार, गंगटोक

संपादकीय पृष्ठ

दूसरी पारी आधा सफर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने जब अपनी दूसरी पारी का आधा सफर पूरा कर लिया है, तब इस पड़ताल का यह बिल्कुल मुफीद वक्त है कि देश की उम्मीदों पर यह सरकार कितनी खरी उतरी और शेष बचे समय में इससे क्या अपेक्षाएं रहेंगी! इसमें कोई दोराय नहीं कि प्रचंड बहुमत के साथ मई 2019 में सत्ता में वापसी करने वाली मोदी सरकार का आत्मविश्वास शुरुआती महीनों में चरम पर था और उसने कई ऐसे काम किए, जो इतिहास में दर्ज किए जाएंगे। खासकर, जम्मू-कश्मीर के सांविधानिक दर्जे में तब्दीली और अनुच्छेद-370 की समाप्ति का साहसिक फैसला! इसी तरह, दशकों से लटके राम जन्मभूमि विवाद में भी नई सरकार ने अतिरिक्त सक्रियता दिखाई और अंतत: इसका न्यायिक निपटारा संभव हुआ। सांप्रदायिक सौहार्द के माहौल में भव्य राममंदिर का शिलान्यास भी इस सरकार की उपलब्धियों में दर्ज हुआ।

जिस गति से सरकार कदम उठाए जा रही थी, ऐसा लगने लगा था कि दूसरी पारी के आधे वक्त में ही वह अपने घोषणापत्र के शायद सारे वादे पूरे कर देगी, हालांकि दिल्ली दंगे व सीएए के खिलाफ शाहीन बाग प्रदर्शन जैसी कुछ चुनौतियां भी उसके सामने आईं, लेकिन उसकी रफ्तार में सबसे बड़ी बाधा के रूप में मार्च 2020 में कोरोना महामारी आई। हालांकि, यह एक वैश्विक समस्या थी औरपूरी दुनिया में विकास का पहिया थम-सा गया था, लेकिन एक विशाल आबादी वाले देश के नाते अन्य देशों के मुकाबले भारत के लिए यह कहीं बड़ी चुनौती बनकर आई। आजाद भारत की किसी सरकार का साबका ऐसी चुनौती से नहीं पड़ा था। जाहिर है, ऐसे ही मौकों पर देश के राजनीतिक नेतृत्व की परीक्षा भी होती है। प्रधानमंत्री मोदी इस विषम समय में एक तरफ देशवासियों को धैर्य की डोर थामे रहने के लिए प्रेरित करते रहे, तो दूसरी ओर सरकार ने लगभग 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त राशन मुहैया कराने का फैसला किया। महामारी काल में जिस तरह से गरीबों की संख्या बढ़ी, इस एक फैसले से देश के हाशिये के लोगों को खास तौर पर बड़ी राहत मिली है। बडे. पैमाने पर टीकाकरण ने भी लोगों के भरोसे को मजबूत किया।

इस आधे सफर के जिस एक प्रकरण को यह सरकार कभी याद नहीं करना चाहेगी, वह निस्संदेह तीन कृषि कानूनों और किसान आंदोलन से जुड़ा है। अब जब ये कानून निरस्त हो चुके हैं, तब किसानों से अन्य मसलों पर भी उसे बात करनी चाहिए। यही लोकतंत्र का तकाजा भी है। बहरहाल, अब जो शेष आधा कार्यकाल बचा है, उसमें एनडीए सरकार के आगे सबसे बड़ी चुनौती रोजगार पैदा करने की होगी। चंद रोज पहले ही प्रकाशित एक सर्वे व्हाट वरीज द वर्ल्ड ने इस वक्त देश की सबसे बड़ी चिंता बेरोजगारी बताई है। लगभग 44 प्रतिशत भारतीयों ने इसे सबसे बड़ी समस्या के रूप में दर्ज किया है।

इसलिए सरकार को इस मोर्चे पर गंभीर प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि उसके पास अब कम वक्त है। उसके हक में अच्छी बात यह है कि अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पर लौट रही है। मार्च 2021 में अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की अर्थव्यवस्था को नकारात्मक श्रेणी में रखा था, उसने अब अपनी रैंकिंग में सुधार करते हुए इसे उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करने वाली इकोनॉमी कहा है। सरकार को इस उम्मीद को थामे अब आगे बढ़ना है।

त्रिपुरा निकाय चुनाव का संदेश

अवधेश कुमार

त्रिपुरा के स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा की जबर्दस्त विजय ने विपक्ष के साथ पूरे देश को चौंकाया है। पश्चिम बंगाल में भारी विजय के पश्चात ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने त्रिपुरा को जिस दिन से अपना दूसरा प्रमुख राजनीति का केंद्र बिंदु बनाया था और पूरी आक्रामकता से वहां सदस्यता अभियान और चुनाव प्रचार अभियान चलाया था, उससे लगता था कि वहां भाजपा को अच्छी चुनौती मिलेगी। चुनाव परिणामों ने इसे गलत साबित किया है।

राजधानी अगरतला नगर निगम सहित कुल 24 नगर निकायों के चुनाव हुए। इनके 334 वार्डों में से भाजपा ने 329 पर विजय प्राप्त की। किसी भी पार्टी की इससे अच्छी सफलता कुछ हो ही नहीं सकती। तृणमूल कांग्रेस को पूरे चुनाव में केवल एक सीट मिली! पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद से पूरे देश में माहौल बनाया गया था कि भाजपा के पराभव की शुरुआत हो चुकी है और कम से कम पूर्वोत्तर में तृणमूल उसे पटखनी देने की स्थिति में आ गई है।

ऐसे में विचार करना पड़ेगा कि राजनीति में भाजपा के विरुद्ध जिस तरह के विरोधी वातावरण या माहौल की बात की जाती है, वैसा हो क्यों नहीं पाता? तृणमूल ने वहां माकपा को स्थानापन्न कर भाजपा के बाद दूसरा स्थान प्राप्त किया है। बावजूद दोनों के बीच मतों में इतनी दूरी है, जिसमें यह कल्पना करना व्यावहारिक नहीं लगता कि 2023 के चुनाव आते-आते उसे पाट दिया जाएगा। अभी 2023 के बारे में किसी प्रकार की भविष्यवाणी उचित नहीं होगी।

लेकिन यह स्वीकार करना पड़ेगा कि त्रिपुरा के स्थानीय निकाय चुनाव को न केवल तृणमूल कांग्रेस, बल्कि संपूर्ण देश के भाजपा विरोधियों ने बड़े चुनाव के रूप में परिणत कर दिया था। बांग्लादेश में हिंदुओं और हिंदू स्थलों पर हिंसात्मक हमले के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान हुई छोटी-सी घटना को जिस तरह बड़ा बनाकर प्रचारित किया गया, उसका उद्देश्य बिल्कुल साफ था। मामला सोशल मीडिया से मीडिया और न्यायालय तक भी आ गया।

पूरा वातावरण ऐसा बनाया गया, मानो त्रिपुरा की भाजपा सरकार के संरक्षण में हिंदुत्ववादी शक्तियां वहां अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों के विरुद्ध हिंसा कर रही हैं और पुलिस या स्थानीय प्रशासन उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। कल्पना यही थी कि त्रिपुरा में भी पश्चिम बंगाल दोहराया जा सकता है।

वास्तव में पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद अभी तक विपक्ष की कल्पना वैसे ही लगती है, जैसे कांग्रेस ने 2018 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव में विजय के बाद मान लिया कि भाजपा पराभव की ओर है तथा राहुल गांधी के नेतृत्व में उसका पुनरोदय निश्चित है। 2019 लोकसभा चुनाव परिणामों ने इस कल्पना को ध्वस्त कर दिया। पश्चिम बंगाल संपूर्ण हिंदुस्तान नहीं है। जरा सोचिए, अगर त्रिपुरा जैसा पड़ोसी छोटा राज्य पश्चिम बंगाल की राजनीति का अंग नहीं बना, तो पूरा देश कैसे बन जाएगा?

पश्चिम बंगाल का राजनीतिक वातावरण, सामाजिक-सांप्रदायिक समीकरण अलग है। करीब तीस फीसदी मुस्लिम मतदाता और विचारों से वामपंथी सोच वाली जनता के एक बड़े समूह के रहते हुए भाजपा के लिए बंगाल में संपूर्ण विजय आसान नहीं है। वहां भाजपा को मुस्लिम विरोधी सांप्रदायिक फासिस्टवादी बताने का असर मतदाताओं पर होगा। इनमें से एक वर्ग भाजपा के विरुद्ध आक्रामक होकर मतदान में काम करेगा। ऐसा सब जगह नहीं हो सकता।

भारत में ऐसे अनेक राज्य हैं, जहां भाजपा के विरुद्ध यही प्रचार उसके पक्ष में जाता है। आप एक समूह को भाजपा के विरुद्ध बताते हैं, तो दूसरा बड़ा समूह एकमुश्त होकर उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है।

जाहिर है, विरोधियों को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना चाहिए। हालांकि वे करेंगे नहीं। दूसरे, इससे यह भी धारणा गलत साबित हुई है कि जमीनी वास्तविकता के परे केवल हवा बनाने या माहौल बनाने से चुनाव जीता जा सकता है। त्रिपुरा ने दिखाया कि बाहर भले आप माहौल बना दीजिए कि भाजपा खत्म हो रही है और तृणमूल कांग्रेस उसकी जगह ले रही है, मगर जमीन पर ऐसा नहीं था।

एमएसपी है रार की असल वजह

चौधरी पुष्पेन्द्र सिंह

पिछले साल कृषि क्षेत्र में लाए गए तीन कानूनों के निरस्तीकरण और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की वैधानिक गारंटी की दो मूल मांगों को लेकर किसानों का एक व्यापक और अभूतपूर्व आंदोलन देशभर में चल रहा है।

आज संविधान दिवस 26 नवम्बर के अवसर पर इस आंदोलन का एक साल पूरा हो गया है। जब किसान तमाम विषम परिस्थितियों को सहते हुए भी पीछे नहीं हटे तो अंतत: मोदी सरकार ने 19 नवम्बर को इन तीन कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी, परंतु किसान मोर्चे ने अपनी अन्य मांगों को लेकर आंदोलन को और तेज करने का निर्णय लिया है।

किसानों की मांग है कि घोषित एमएसपी से नीचे फसलों की खरीद कानूनी रूप से वर्जित हो, यानी कोई भी व्यक्ति, व्यापारी या संस्था जब फसलों का क्रय करे तो एमएसपी वैधानिक रूप से आरक्षित मूल्य हो जिससे कम मूल्य पर कोई खरीद ना हो।

एमएसपी का निर्धारण भी कृषि लागत मूल्य आयोग की ड.2 लागत पर 50 प्रतिशत मुनाफा जोड़कर होना चाहिए जैसा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश थी और भाजपा का वायदा था। एमएसपी की गारंटी की यह मांग किसानों विशेषकर छोटे किसानों के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इस मांग के गणित को समझना बहुत आवश्यक है। अभी देश में 23 फसल की एमएसपी घोषित होती है। इसमें मुख्य रूप से खाद्यान्न-गेहूं, धान, मोटे अनाज, दालें; तिलहन, गन्ना व कपास जैसी कुछ नकदी फसल शामिल हैं। दूध, फल, सब्जियों, मांस, अंडे आदि की एमएसपी घोषित नहीं होती।

2019-20 में इन फसल का एमएसपी पर कुल मूल्य लगभग 11 लाख करोड़ रुपये था। इसमें से गन्ने की फसल की खरीद सरकारी घोषित रेट पर मुख्यत: निजी मिलें करती रही हैं। अत: गन्ने को इस गणना से अलग करके बाकी 22 फसल की कीमत लगभग 10 लाख करोड़ रुपये बनती है। किसान देश की आधी आबादी है अत: वह स्वयं भी बहुत बड़ी मात्रा में इन फसल का उपभोक्ता है।

इन फसल में से किसान लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपये मूल्य की फसल अपने स्वयं के उपभोग में, अपने पशुओं के आहार में, अगली फसल के बीज आदि में इस्तेमाल कर लेता है। कुछ हिस्सा खराब भी हो जाता है। अत: गन्ना छोड़कर एमएसपी वाली फसल में से लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपये मूल्य की फसल ही बाजार में बिक्री हुई। इसमें से सरकारी खरीद लगभग 2.75 लाख करोड़ रुपये मूल्य की फसल की हुई। बाकी लगभग 3.75 लाख करोड़ रुपये के मूल्य की फसल ही निजी क्षेत्र द्वारा खरीदी गई। एक अनुमान के अनुसार निजी व्यापारी एमएसपी से औसतन 20 प्रतिशत कम मूल्य पर फसल खरीदते हैं, अत: किसानों को इन फसल के लगभग तीन लाख करोड़ रुपये ही मिले। अब किसानों की मांग यह है कि ये निजी व्यापारी भी एमएसपी पर ही फसल खरीदें, यह नहीं है कि सारी फसल सरकार खरीदे।

सरकार को केवल खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार या अपनी आवश्यकता की मात्रा ही खरीदनी होगी। किसानों की मांग निजी क्षेत्र या सरकार द्वारा किसानों की सारी फसल खरीदने के लिए बाध्य करना नहीं हैं, परन्तु यदि कोई निजी व्यापारी या सरकार बाजार में उतरते हैं तो वह किसान को एमएसपी वाली कीमत देने के लिए अवश्य कानूनी रूप से बाध्य हों। यदि इस मांग को मान लिया जाता है तो सरकार के ऊपर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा, केवल निजी व्यापारी जो अब तक किसानों का आर्थिक शोषण करते रहे हैं उस पर अंकुश अवश्य लग जाएगा। यदि यह कानून बने तो उपरोक्त वर्ष की गणना में किसानों को निजी व्यापारियों से 75,000 करोड़ रुपये और मिलते। यही मूलभूत लड़ाई है।

प्रश्न यह है कि सरकार इस मांग पर अपने पैर क्यों घसीट रही है, जबकि उसका एक रु पया भी इसमें अतिरिक्त खर्च नहीं होना है। उल्टे यह अतिरिक्त धनराशि किसानों के हाथ में पहुंचने से अर्थव्यवस्था में मांग, रोजगार, कालांतर में निवेश और सरकार का टैक्स बढ़ेगा। कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि एमएसपी निजी क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं किया जा सकता, परन्तु ऐसे तमाम उदाहरण हैं जहां जनहित या वर्गहित में, आर्थिक व सामाजिक कारणों से सरकार सेवाओं या वस्तुओं का मूल्य निर्धारित या नियंत्रित करती है तो किसानों की आर्थिक सुरक्षा के लिए फसल का न्यूनतम मूल्य निर्धारित क्यों नहीं किया जा सकता।

अभी हाल ही में सबसे ताजा उदाहरण कोरोना की वैक्सीन व इसके इलाज में लगने वाली अन्य दवा के मूल्य को निर्धारित करने का है। वास्तव में एमएसपी मूल्य किसानों का अधिकार है जो अब तक उन्हें नहीं दिया गया।

भारत की विकास यात्रा

पत्रलेखा चटर्जी

जो लोग भारत की विकास यात्रा पर नजर रखते हैं, उनके लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के आंकड़े जारी होना एक बड़ी घटना है। वर्ष 1992-93 से, जब इस तरह का पहला सर्वेक्षण किया गया था, एनएफएचएस लगातार सामाजिक-आर्थिक और स्वास्थ्य संकेतकों के साथ-साथ देश में उभरते मुद्दों पर महत्वपूर्ण आंकड़ा प्रदान कर रहा है।

यह आंकड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन महत्वपूर्ण चुनौतियों को चिह्नित करता है, जो जमीनी धरातल पर हुई प्रगति के साथ-साथ अब भी बनी हुई हैं। एनएफएचएस के ताजे आंकड़े मिले-जुले हैं। बाईस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किए गए एनएफएचएस-5 सर्वेक्षण के पहले चरण के निष्कर्ष दिसंबर, 2020 में जारी किए गए थे। अब पांचवें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के दूसरे और अंतिम चरण के बहुप्रतीक्षित आंकड़े सामने आ गए हैं।

दूसरे चरण के सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे भारत के कुछ सबसे बड़े राज्य शामिल हैं। एनएफएचएस-5 सर्वेक्षण का फील्डवर्क दो चरणों में आयोजित किया गया था-पहला चरण 17 जून, 2019 से 30 जनवरी, 2020 तक 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में, और दूसरा चरण दो जनवरी, 2020 से 30 अप्रैल, 2021 तक 14 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में आयोजित किया गया था।

सबसे पहले अच्छी खबर। भारत ने जनसांख्यिकीय मामले में एक प्रमुख उपलब्धि हासिल की है। रिकॉर्ड स्तर पर पहली बार, देश की प्रजनन दर (टीएफआर) राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्थापन दर 2.1 से नीचे आ गई है। राज्यों के बीच अंतर अब भी कायम है, लेकिन हम जनसंख्या स्थिरीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरी अच्छी खबर यह है कि समग्रता में कई अन्य स्वास्थ्य संकेतकों और अन्य क्षेत्रों, जो स्वास्थ्य एवं कल्याण को प्रभावित करते हैं, में सुधार हुआ है।

उदाहरण के लिए, बिजली की सुविधा वाले घरों में रहने वालों की संख्या एनएफएचएस-4 (2015-2016) के 88 फीसदी के मुकाबले बढ़कर एनएफएचएस-5 (2019-2021) में 96.8 फीसदी हो गई है। आज बहुत ज्यादा महिलाओं के पास बैंक खाते हैं। इसी अवधि के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर संस्थागत जन्म भी 79 फीसदी से बढ़कर 89 फीसदी हो गया है।

अखिल भारतीय स्तर पर, नाटे कद के बच्चों की संख्या 38 फीसदी से घटकर 36 फीसदी हो गई है; कमजोर शारीरिक अंगों वाले बच्चों की संख्या 21 फीसदी से घटकर 19 फीसदी रह गई है; और कम वजन वाले बच्चों की संख्या 36 फीसदी से घटकर 32 फीसदी रह गई है। दिलचस्प बात यह है कि दूसरे चरण (महामारी के दौरान) में इकट्ठा किए गए राज्यों के आंकड़े महामारी की शुरुआत से पहले एकत्र किए गए पहले चरण के आंकड़ों की तुलना में कुछ मोर्चों पर ज्यादा सकारात्मक दिखते हैं।

ऐसा क्यों है, इसके बारे में अब तक हम नहीं जानते। लेकिन खुशखबरी से हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। प्रमुख मोर्चों पर स्थिति और भी खराब हुई है। बच्चों और महिलाओं में एनीमिया सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है। यह एक पुरानी समस्या है और एनीमिया मुक्त भारत अभियान चलाए जाने के बावजूद यह एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है।

पांच वर्ष से कम उम्र के एनीमिया पीड़ित बच्चों की संख्या वर्ष 2015-2016 के 58.6 फीसदी के मुकाबले वर्ष 2019-2021 में बढ़कर 67.1 फीसदी हो गई है। बच्चों के पोषण को लेकर चिंता का एक अन्य कारण यह है कि ताजा एनएफएचएस सर्वे में जिस गति से अविकसित और कम वजन वाले बच्चों की संख्या घटी है, वह वर्ष 2005-06 और वर्ष 2015-16 के सर्वेक्षणों की दर से कम है।

आधे से अधिक बच्चे और महिलाएं (गर्भवती महिलाओं सहित) एनएफएचएस -4 की तुलना में दूसरे चरण में राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों और अखिल भारतीय स्तर पर एनीमिक पाए गए, जबकि गर्भवती महिलाओं द्वारा 180 दिन या उससे अधिक समय तक आयरन फोलिक एसिड (आईएफए) गोलियों के सेवन में पर्याप्त बढ़ोतरी देखी गई।

हिंदी पट्टी में एनीमिया एक गंभीर समस्या है।

मसलन मध्य प्रदेश में छह से 59 महीने के एनीमिया पीड़ित बच्चों की संख्या 68.9 फीसदी (एनएफएचएस-4) से बढ़कर (एनएफएचएस-5 में) 72.7 फीसदी हो गई है। उत्तर प्रदेश में, हालांकि नाटे कद और कमजोर अंगों वाले बच्चों की संख्या में मामूली कमी आई है, लेकिन छह से 59 महीने के बीच के एनीमिया पीड़ित बच्चों की संख्या 63.2 फीसदी (एनएफएचएस-4) से बढ़कर 66.4 फीसदी (एनएफएचएस-5) हो गई है।

चूंकि हमारे पास अब तक सभी राज्यों का कच्चा डेटा नहीं है, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि देश भर में बच्चों और वयस्कों में एनीमिया इतना अधिक क्यों है। एनीमिया, जो कम ऊर्जा और कई अन्य लक्षणों का कारण बनता है, कई वजहों से बना रह सकता है और केवल भोजन की मात्रा के कारण नहीं होता है। स्वच्छ पानी और स्वच्छता की उपलब्धता भी एनीमिया को प्रभावित करती है, लेकिन यह देखते हुए कि खुले में शौच कम हो रहा है और अधिक लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जा रहा है, हमें यह जानने की जरूरत है कि इसके दूसरे कारण क्या हैं और कहां हैं।

पोषण विशेषज्ञों का कहना है कि इसका एक कारण अधिकांश भारतीयों के लिए आहार विविधता और अपर्याप्त आयरन युक्त भोजन की कमी है। हमें अपने लोगों के दैनिक आहार के बारे में और अधिक सूक्ष्म-स्तरीय डेटा की आवश्यकता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण वास्तव में सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में वर्गीकृत विटामिन और खनिजों के सेवन में कमियों पर प्रकाश नहीं डालता है।

एनीमिया के साथ-साथ हम मोटापे में भी वृद्धि का सामना कर रहे हैं। वर्ष 2015-2016 में 20.6 फीसदी महिलाएं मोटापे से ग्रस्त थीं, जबकि अब 24 फीसदी महिलाएं मोटापे से ग्रस्त हैं और इसी अवधि के दौरान मोटापे से ग्रस्त पुरुषों की संख्या 18.9 फीसदी से बढ़कर 22.9 फीसदी हो गई है। इसका मतलब है कि बड़े पैमाने पर भारतीय अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं या समझदारी से खाना नहीं खाते हैं।

हवाई अड्डे, बुलेट ट्रेन और राजमार्ग भारत की विकास गाथा का एक हिस्सा हैं। इसका दूसरा हिस्सा है-मानव विकास, जो उतना ही महत्वपूर्ण है। उपलब्धियों की सराहना करते हुए यह जरूरी है कि हम अधूरे कार्यों और भारत के लाखों बच्चों और वयस्कों के बीच एनीमिया और भूख जैसी समस्याओं पर अधिक ध्यान दें।

कानपुर देहात में पेशी पर आया रेप का आरोपित फरार

कानपुर, 30 नवम्बर (एजेन्सी)। जिला जेल से पेशी पर माती कोर्ट लाया गया कानपुर नगर का रहने वाला रेप का आरोपित सोमवार को पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। इससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। देर रात उसकी तलाश हुई, पता न चलने पर उसको लाने वाले सिपाही के खिलाफ मुदकमा दर्ज कर किया गया है।

कानपुर के मसवानपुर का रहने वाला पवन उर्फ गुड्डू 25 फरवरी को अकबरपुर कोतवाली के एक गांव में अपनी चचेरी बहन के घर आया था। शाम को उसने घर के बाहर खेल रही भांजी को खेतों पर ले जाकर दुष्कर्म किया। उसको गंभीर हालत में खेत पर ही छोड़कर फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपित को दूसरे दिन तमंचे के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था। सोमवार को हत्या के प्रयास मामले में उसको जेल से जिला जज की कोर्ट में पेशी पर लाया गया था। वह पेशी पर ले जा रहे सिपाही अहमद खां को चकमा देकर फरार हो गया। खबर मिलते ही अकबरपुर कोतवाल पुलिस के साथ कचहरी पहुंचे और फरार बंदी की तलाश शुरू कराई, लेकिन पता नहीं चल सका। एसपी केशव कुमार चौधरी ने बताया कि अकबरपुर पुलिस के साथ एसओजी को फरार बंदी की गिरफ्तारी का निर्देश दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद लापरवाही में बंदी को कोर्ट में पेश करने ले गए सिपाही को निलंबित किया जाएगा।

विपक्ष की अनुपस्थिति में राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित

नई दिल्ली, 30 नवम्बर (एजेन्सी)। राज्यसभा की कार्यवाही मंगलवार को दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। यह फैसला तब लिया गया, जब विपक्ष ने सभापति एम. वेंकैया नायडू की ओर से 12 सांसदों के निलंबन को वापस लेने से इनकार करने पर बहिर्गमन किया।

उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह से विपक्ष की अनुपस्थिति में सदन को स्थगित करने का अनुरोध करते हुए, संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा, 'हमारी लोकतांत्रिक सरकार है और हमारे नेता भी बहुत लोकतांत्रिक हैं, इसलिए हम विपक्ष के बिना सदन नहीं चलाना चाहते हैं। उन्होंने एक दिन के लिए इसका बहिष्कार किया है, इसलिए उन्हें कल वापस आने दें, ताकि हम विधेयकों को ला सकें। सरकार रचनात्मक आलोचना के लिए तैयार है।' इसके बाद उपसभापति ने सदन की कार्यवाही बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

इससे पहले सदन के नेता पीयूष गोयल ने विपक्ष की आलोचना की और अध्यक्ष के फैसले को सही ठहराया और उन घटनाओं की श्रृंखला को फिर से बताया, जिनके कारण उनका निलंबन हुआ। उन्होंने कहा, 'सदन की पवित्रता की रक्षा के लिए कार्रवाई की आवश्यकता थी, क्योंकि विपक्षी सांसदों के एक वर्ग ने पिछले मानसून सत्र के दौरान हंगामा किया था, महिला मार्शलों पर हमला किया था और सदन में तोड़फोड़ करने की कोशिश की थी।' नायडू ने मंगलवार को निलंबन रद्द करने की विपक्ष की अपील को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, 'मैं विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की 12 सांसदों के निलंबन को रद्द करने की अपील पर विचार नहीं कर रहा हूं, जब तक कि दोषी सदस्य अपने कदाचार के लिए माफी नहीं मांगते और सदन सुचारू रूप से नहीं चलता।' इस पर विपक्षी सदस्यों ने वॉक आउट कर दिया। खड़गे ने नियम 256 के तहत यह मुद्दा उठाते हुए कहा था कि निलंबन सदन के नियमों के विपरीत है।

विपक्ष के नेता ने कहा, 'सदस्यों को पिछले सत्र में हुए एक आचरण पर निलंबित कर दिया गया है और यह सदन के नियमों के खिलाफ है।' उन्होंने कहा कि माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता।

आसान और लाभकारी बिजनेस है मत्स्य पालन कॅरियर के हैं भरपूर अवसर

2 से 3 मिनट के बाद मछली के बच्चों को तालाब में डाल देना चाहिए। ध्यान रखने वाली बात यह है कि मछलियों की मात्रा तालाब में ना तो बहुत ज्यादा होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। आप तालाब में सही अनुपात में मछलियों का बीज डालें।

भारत भर में मत्स्य पालन एक जाना पहचाना व्यवसाय रहा है। कृषि से इसको जोड़कर जरूर देखा जाता रहा है, किंतु हकीकत में यह काफी उन्नत और लाभकारी व्यवसाय है। वर्तमान में कोरोनावायरस के कारण बड़ी संख्या में गांवों की ओर लोगों का पलायन हुआ है। कई लोगों को रोजगार की समस्या भी उत्पन्न हुई है, क्योंकि जमे जमाए व्यवसाय या फिर शहर में करने वाली नौकरी छूटने के बाद लोग गांव की ओर लौटे हैं। गांव में चूँकि अधिकतर लोगों के पास कम-अधिक जमीन होती ही है और ऐसी स्थिति में मत्स्य पालन उन सबके लिए एक लाभकारी व्यवसाय हो सकता है।

तालाब को ठीक से करें तैयार

अक्सर लोग किसी तालाब की खुदाई के बाद तुरंत ही मछली के बीज डाल देते हैं, लेकिन यह ठीक मेथड नहीं है। सबसे पहले तालाब की सफाई करने के बाद उसमें 200 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से चूने का छिड़काव जरूरी है। इसके अलावा महुए की खली और ब्लीचिंग पाउडर डालने से भी मछली पालन के लिए तालाब बेहतर कंडीशन में तैयार हो जाता है। यह सारा कार्य आप ठंड के मौसम में ही कर लें, ताकि ठंड का मौसम बीतते-बीतते मछली का बच्चा डालने योग्य आप का तालाब तैयार हो जाए। साथ ही तालाब में ढैंचा नामक घास भी बोया जाता है, ताकि बाद में वह खाद बन जाए और मछली पालन के लिए उपयुक्त रहे। यह तकरीबन 40 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से तालाब में बोया जाता है। साथ ही गोबर की खाद डालने से भी वनस्पति जल्दी उग जाती है। अगर समय पर तालाब में अच्छी घास नहीं होती है तो गोबर के साथ सुपर फास्फेट और यूरिया का घोल तालाब में डालना लाभकारी हो सकता है। हालांकि मछली का बीज डालने से काफी पहले ही यह कार्य करना चाहिए। मछली का बीज डालने के बाद खाद डालना खतरनाक हो सकता है। उपरोक्त कार्य करने के कम से कम 1 महीने बाद ही तालाब में पानी भरकर, ठंड का मौसम बीतने के बाद मछली का बीज डालें। साथ ही तालाब के पानी की गुणवत्ता और उस में ऑक्सीजन की ठीक मात्रा हो, इसके प्रति अतिरिक्त सजगता आवश्यक है।

मछलियों की ब्रीड पर खास ध्यान दें

अगर आपका तालाब ठीक ढंग से तैयार हो गया है, किंतु मछलियों के बीज आप सही ढंग से नहीं डालते हैं, तो आपके लिए यह लाभकारी नहीं रहेगा। मुख्य रूप से देशी और विदेशी ब्रीड की मछलियां लोग डालते हैं। इसमें देसी में रोहू, कतला, मृगल इत्यादि प्रचलित प्रजातियां हैं, तो विदेशियों में सिल्वर कॉर्प, ग्रास कार्प इत्यादि प्रमुख हैं। कई लोग जब बाहर से मछली लेकर आते हैं तो उसे एक दो परसेंट नमक के घोल में कुछ देरी के लिए रखते हैं, ताकि अगर मछली के बीज में कोई बीमारी है तो उसका असर कम हो जाए। हालांकि यह बहुत देर तक नहीं होना चाहिए और 2 से 3 मिनट के बाद मछली के बच्चों को तालाब में डाल देना चाहिए। ध्यान रखने वाली बात यह है कि मछलियों की मात्रा तालाब में ना तो बहुत ज्यादा होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। आप तालाब में सही अनुपात में मछलियों का बीज डालें। अगर एक या दो मछली आपके तालाब में मर जाती हैं, तो उसे तत्काल निकाल कर बाहर करें समय-समय पर बीज की वृद्धि और उसकी जांच करना आपको नुकसान से बचा सकता है। मछलियों के लिए यूं तो किसी विशिष्ट चारे की जरूरत नहीं होती है, खासकर तब जब आप का तालाब पुराना हो गया हो, किंतु चावल का आटा और मूंगफली की खली इत्यादि मछलियों को तेजी से बढ़ाती हैं। इसके अलावा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा युक्त चारे की मात्रा मछलियों के लिए पर्याप्त रूप से उपलब्ध हो, इसके प्रति भी सजग रहें। ध्यान दें मछली का बीज सही क्वालिटी का हो, तो सही मात्रा में भी अवश्य हो, अन्यथा बाद में मछलियां ठीक ढंग से बढ़ेंगी नहीं।

मार्केट को समझना जरूरी है

अब जब आपके पास मछली के बीज तैयार हो जाते हैं तो आसपास की मार्केट का एक अध्ययन जरूर करें और देखें कि आपके आसपास किस तरह की मछलियों की खपत ज्यादा होती है। लोग आखिर क्या खरीदते हैं?

ऐसे में जब आप मछली मार्केट जाएंगे, तो एक ग्राहक बनकर मछलियों की ब्रीड से लेकर उसकी कीमत तक का पता कर सकते हैं। उसी अनुरूप आप अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाएं। अगर बड़ी मछलियों की खपत अधिक है, तब आपके तलाब में कम मछलियों का बीज रहना चाहिए, जबकि अगर छोटी मछलियों की खपत है तो तालाब में बीज अगर अधिक भी डालेंगे तो आपको फायदा ही होगा। कुल मिलाकर सही टाइम पर मछलियों को बेचना और सही व्यापारियों से संपर्क में रहना आपको लाभ दिला सकता है। कई बार मछली के व्यापारी आपके तालाब पर आकर खुद ही सारी मछलियां ले जाते हैं। हालांकि रेट में अगर ज्यादा डिफरेंस है तो आप मछलियों को खुद भी मार्केट तक पहुंचा सकते हैं।

इसके अलावा कुछ और बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे मछलियों की ग्रेडिंग करना आवश्यक है। मतलब अगर आपके तालाब में कुछ मछलियां बड़ी हो गई हैं और कुछ मछलियां छोटी हैं, तो बड़ी मछलियों को या तो निकाल कर दूसरे तालाब में डालें या उन्हें मार्केट में भेज दें, क्योंकि बड़ी मछलियों का आहार अधिक होगा और वह छोटी मछलियों का चारा भी खा जाएंगी। इसलिए मछलियों की ग्रेडिंग करना आवश्यक है ताकि मछलियों की ग्रोथ में एक निरंतरता रहे। साथ ही मछलियों में इंटरनल और एक्सटर्नल बीमारी के प्रति सजग रहें, अन्यथा आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी पूँजी भारी नुक्सान में बदल गयी। इसके अलावा नई नई जानकारियां आप भिन्न माध्यमों से लेते रहें और अलग-अलग मछली पालकों के संपर्क में रहें। ऐसे में नई चीजें आपको पता चलेंगी।

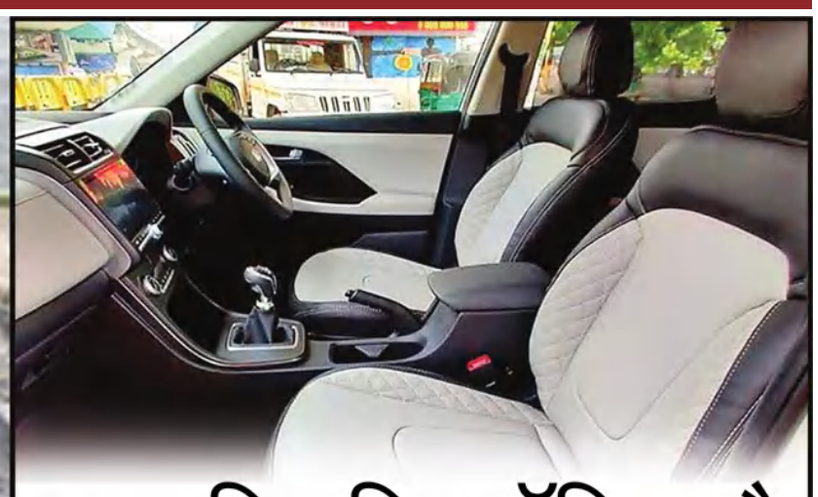

बहुत क्रिएटिव कॅरियर है कार एसेसरीज डिजाइनिंग

एक कार एसेसरीज डिजाइनर बनने के लिए डिजाइन के प्रासंगिक विशेषज्ञता में कम से कम स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। आप बैचलर ऑफ डिजाइन, बीएससी इन डिजाइन, बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, बी डीएस इन ऑटोमोटिव डिजाइन करके इस क्षेत्र में कदम रख सकते हैं।

कार एसेसरीज डिजाइनिंग एक ऐसा कॅरियर क्षेत्र है, जिसके बारे में बेहद कम लोगों को ही जानकारी होती है। लेकिन यह एक ऐसा क्रिएटिव कॅरियर क्षेत्र है, जिसमें ग्रोथ की संभावना बहुत अधिक है। यह एक ऑटोमोबाइल डिजाइनर के काम का एक हिस्सा है, लेकिन यह केवल कारों और इसके सामान के लिए पूरा करता है। कार एक्सेसरी डिजाइनर ऐसे व्यक्ति हैं जो कार एक्सेसरीज और पाट्र्स के लिए नए डिजाइन बनाते हैं। वे न केवल देखभाल की संरचना में सुधार करते हैं, बल्कि इसकी कार्यक्षमता भी बढ़ाते हैं। ऐसा करते समय, एक कार एक्सेसरी डिजाइनर को वाहन की सुरक्षा को ध्यान में रखना चाहिए और दिए गए मापदंडों के तहत काम करना चाहिए। तो चलिए आज हम आपको इस कॅरियर क्षेत्र के बारे में विस्तारपूर्वक बता रहे हैं-

क्या होता है काम

एक कार एसेसरीज डिजाइनर तीन क्षेत्रों में से एक में काम करते हैं- इंटीरियर डिजाइनिंग, एक्सटीरियर डिजाइनिंग या कलर और ट्रिम डिजाइन। वे ड्राइंग, मॉडल और प्रोटोटाइप का उपयोग करके कार एक्सेसरी पाट्र्स, असेंबली और सिस्टम के ड्राफ्टिंग डिजाइन बनाते हैं। उनका मुख्य काम होता है कि वे कार को विजुअली अधिक अपीलींग बनाएं।

स्किल्स - कॅरियर एक्सपर्ट बताते हैं कि एक कार एसेसरीज डिजाइनर को हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल सिस्टम के बारे में विस्तृत जानकारी होनी चाहिए जो वाहन में उपयोग होने जा रहे हैं। इसके अलावा उन्हें ग्राहक की पूरी आवश्यकता को समझना चाहिए और डिजाइन और इसके उत्पादन के उपयोग के बारे में बड़े पैमाने पर शोध करना चाहिए। उनके भीतर कुछ अलग व हटकर सोचने की क्षमता होनी चाहिए। साथ ही कंप्यूटर व कार का तकनीकी ज्ञान उनके काम को अधिक आसान बनाता है।

योग्यता - एक कार एसेसरीज डिजाइनर बनने के लिए डिजाइन के प्रासंगिक विशेषज्ञता में कम से कम स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। आप बैचलर ऑफ डिजाइन, बीएससी इन डिजाइन, बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, बी डीएस इन ऑटोमोटिव डिजाइन करके इस क्षेत्र में कदम रख सकते हैं। जिस विश्वविद्यालय या कॉलेज से उम्मीदवार अपनी डिग्री हासिल करता है, उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए।

आमदनी - कॅरियर एक्सपर्ट बताते हैं कि इस क्षेत्र में आमदनी आपके अनुभव व क्रिएटिविटी के आधार पर बढ़ती जाती है। हालांकि एक कार एसेसरीज डिजाइनर की एवरेज सालाना सैलरी सात से आठ लाख के बीच होती है।

प्रमुख संस्थान

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नवी मुंबई
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद
एरिना एनिमेशन, बैंगलोर
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, बैंगलोर
फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, नोएडा
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, चेन्नई
वीआईडीएम इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एंड मैनेजमेंट, नई दिल्ली
वाईएमसीए इंस्टीट्यूट फॉर ऑफिस मैनेजमेंट, नई दिल्ली

ऑपरेशन्स मैनेजमेंट में कॅरियर बनाने के लिए क्या करें?

कॅरियर प्रबंधन प्रक्रिया लक्ष्यों और उद्देश्यों को स्थापित करने के साथ शुरू होती है। यह कार्य थोड़ा कठिन हो सकता है, जब व्यक्ति के पास कॅरियर के अवसरों और उनकी प्रतिभा और क्षमताओं के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है।

ऑपरेशन्स मैनेजमेंट आपके भविष्य के कॅरियर के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संसाधनों के निवेश की एक लंबी प्रक्रिया है। कॅरियर प्रबंधन प्रक्रिया विभिन्न अवधारणाओं को अपनाती है, जैसे- आत्म-जागरूकता, कॅरियर विकास योजना और करियर अन्वेषण, जीवन भर सीखने की क्षमता और नेटवर्किंग। कॅरियर में अर्ध-कुशल से लेकर कुशल और अर्ध पेशेवर से पेशेवर तक के सभी प्रकार के रोजगार शामिल हैं। कॅरियर प्रबंधन प्रक्रिया लक्ष्यों और उद्देश्यों को स्थापित करने के साथ शुरू होती है। यह कार्य थोड़ा कठिन हो सकता है, जब व्यक्ति के पास कॅरियर के अवसरों और उनकी प्रतिभा और क्षमताओं के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है। हालांकि, पूरी करियर प्रबंधन प्रक्रिया परिभाषित लक्ष्यों और उद्देश्यों की स्थापना पर ही आधारित होती है।

ऑपरेशन्स मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य

सामान्य शब्दों में परिचालन प्रबंधन किसी संगठन के लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से एक कुशल तरीके से सामग्रियों और श्रम को वांछित वस्तुओं और सेवाओं में परिवर्तित करने से संबंधित है। यह उपलब्ध संसाधनों की खरीद और उपयोग करके उत्पादन को अधिकतम करता है, जिसमें कच्चे माल, उपकरण, प्रौद्योगिकी, सूचना और अन्य क्षेत्र शामिल हैं। उत्पादन की प्रक्रिया की योजना, डिजाइनिंग, आयोजन, नियंत्रण और अनुकूलन के साथ इसका अधिक सम्बन्ध होता है। संचालन प्रबंधन यह सुनिश्चित करता है कि एक इकाई कुशलतापूर्वक और सफलतापूर्वक इनपुट को आउटपुट में कैसे बदल देती है। यह स्पष्ट है कि संचालन प्रबंधन डिलीवरी ओरिएंटेड होता है। हालांकि, संचालन प्रबंधन को लॉजिस्टिक्स प्रबंधन के समान नहीं माना जाना चाहिए। संचालन प्रबंधन व्यापक है और लॉजिस्टिक्स प्रबंधन इसका एक हिस्सा है। लॉजिस्टिक्स प्रबंधन किसी अभियान, योजना, परियोजना या रणनीति के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए श्रमिकों, सामग्री और अन्य संसाधनों की खरीद, निष्पादन और नियंत्रण की योजना बनाता है। विनिर्माण और सेवा संगठनों दोनों को ही संचालन प्रबंधन के कार्य की आवश्यकता होती है, जो एक प्रक्रिया को शुरू से लेकर अंत तक कवर करता है। सदियों से विनिर्माण उद्योग फल-फूल रहे हैं। अब सेवा क्षेत्र में तेजी के साथ परिचालन प्रबंधकों के लिए अवसर कई गुना बढ़ गए हैं।

ऑपरेशन्स मैनेजमेंट में करियर बनाने के लिए क्या करें?

अन्य विषयों की तरह प्रबंधन शिक्षा में भी कई विषय होते हैं। प्रबंधन के छात्रों को प्रबंधन के सभी प्रमुख विषयों के अवलोकन के साथ संयुक्त रूप से सामान्य प्रबंधन के तहत विषयों और सिद्धांतों से गुजरना पड़ता है। हालांकि, दो साल की स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा में प्रबंधन की एक विशेष शाखा में विशेषज्ञता का प्रावधान है। प्रबंधन की प्रसिद्ध शाखाओं में विपणन, वित्त, मानव संसाधन आदि शामिल हैं। संचालन प्रबंधन के लिए आपको निम्नलिखित कौशल की आवश्यकता होती है:

नेतृत्व
नीति, योजना और रणनीति की समझ
नीतियों और प्रक्रियाओं को विकसित करने, लागू करने और समीक्षा करने की क्षमता
बजट, रिपोर्टिंग, योजना और लेखा परीक्षा की देखरेख करने की क्षमता
आवश्यक कानूनी और नियामक दस्तावेजों की समझ

इसके साथ-साथ आपको इन बातों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है:

सुनिश्चित करें कि आप सही मेट्रिक्स पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं
मुख्य समस्याओं को पहचानने के लिए हमेशा डेटा का उपयोग करें
नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ अप-टू-डेट रहने में विश्वास करें
स्वचालन से पहले प्रक्रियाओं पर ध्यान दें
ध्यान से लोगों के साथ कम्यूनिकेट करें

ऑपरेशन्स मैनेजर बनने के लिए आवश्यकता योग्यता

संचालन प्रबंधक के संबंधित क्षेत्र में कम से कम स्नातक की डिग्री की आवश्यकता होती है। व्यवसाय प्रशासन में स्नातक की डिग्री के साथ, छात्रों को ज्ञान और विपणन योग्य कौशल विकसित करना होता है, जिसे वे अपने कॅरियर के दौरान बना सकते हैं। इसके अलावा, एक संचालन प्रबंधक होने के लिए, किसी के पास मजबूत नेतृत्व और पारस्परिक कौशल, शानदार संचार और ग्राहक की आवश्यकताओं की समझ होनी चाहिए। संचालन प्रबंधक बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता निम्नलिखित है:

विषय संयोजन- किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 वीं कक्षा में कोई भी स्ट्रीम
उम्मीदवारों के पास 10 + 2 + 3 प्रणाली के माध्यम से योग्यता और किसी भी विषय में न्यूनतम 50% अंकों से उत्तीर्ण के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए
उम्मीदवारों के पास ऑपरेशंस मैनेजमेंट में एमबीए (ऑपरेशंस) या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ऑपरेशनल मैनेजमेंट में मास्टर्स डिग्री का भी बहुत महत्त्व होता है

ऑपरेशन्स मैनेजर के जॉब रोल्स

सप्लाई चेन मैनेजर
एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मैनेजर
प्लांट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर
परचेस मैनेजर फैसिलिटी मैनेजर
इन्वेंटरी कण्ट्रोल मैनेजर

रोजगार के अवसर

एक ऑपरेशन मैनेजर के रूप में इस क्षेत्र में कॅरियर बनाने की इच्छा रखने वालों के लिए रोजगार के ढेरों अवसर होते हैं। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में संचालन प्रबंधकों के लिए बहुत स्कोप है। कुछ शीर्ष क्षेत्र इस प्रकार हैं:

स्वास्थ्य कॉर्पोरेट व्यवसाय
बहुराष्ट्रीय कंपनियां हॉस्पिटैलिटी
विनिर्माण और खुदरा वित्तीय संस्थाए
बीमा क्षेत्र सूचना प्रौद्योगिकी
ई-कॉमर्स वेयरहाउसिंग
निर्माण सलाहकारी फर्में

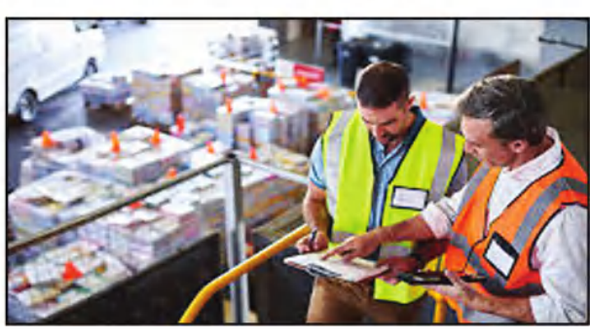

समाचार

शादियों के सीजन में सोने-चांदी के गिरे भाव

नई दिल्ली । शादियों के सीजन के बीच सोना-चांदी के जेवर खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है। सर्राफा बाजारों में आज सोना-चांदी की चमक फीकी पड़ गई है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से अक्रांत माहौल के बीच देश भर के सर्राफा बाजारों में सोना-चांदी के भाव गिर गए है। अब 24 कैरेट शुद्ध सोना अपने ऑल टाइम हाई रेट 56126 रुपये से केवल 8136 रुपये सस्ता है। वहीं, चांदी पिछले साल के अधिकतम रेट 76004 रुपये से 12913 रुपये सस्ती है। आज 24 कैरेट सोना 348 रुपये गिरकर 48118 रुपये पर खुला। जहां तक 22 कैरेट सोने के भाव की बात करें तो आज यह 44076 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट से खुला। वहीं 18 कैरेट गोल्ड की कीमत अब 36089 रुपये पर है। 14 कैरेट का भाव अब 28149 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया है। इस पर 3 फीसद जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से है। वहीं, अगर चांदी की बात करें तो इसका हाजिर भाव 517 रुपये प्रति किलो टूटकर 63095 रुपये पर आ गया है। बता दें कि आईबीजेए द्वारा जारी किए गए रेट देशभर में सर्वमान्य है। हालांकि, इस वेबसाइट पर दिए गए रेट में जीएसटी शामिल नहीं किया गया है। सोना खरीदते-बेचते समय आप के रेट का हवाला दे सकते हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आईबीजेए देशभर के 14 सेंटरों से सोने-चांदी का करेंट रेट लेकर इसका औसत मूल्य बताता है। सोने-चांदी का करेंट रेट या यूं कहें हाजिर भाव अलग-अलग जगहों पर अलग हो सकते हैं पर इनकी कीमतों में थोड़ा अंतर होता है।

पीएम किसान की 10वीं किस्त जारी होने में अब चंद दिन शेष

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री किसान स मान निधि स्कीम की 10वीं किस्त आपके खाते में आने में अब चंद दिन ही शेष रह गए हैं। करीब 12 करोड़ से अधिक किसान इस योजना के तहत रजिस्टर्ड हैं। बड़े पैमाने पर पीएम किसान स मान निधि योजना में अपात्रों की एंट्री के बाद राज्य सरकारों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब इसका फायदा उठाने वाले अपात्रों की अब खैर नहीं। चाहे वह पति-पत्नी दोनों स्कीम का लाभ ले रहे हों या टैक्सपेयर्स, पेंशनधारक, सभी अपात्रों से वसूली होगी और उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। अगर पिछली 9 किस्तों पर नजर डालें तो सरकार भी अब पति-पत्नी दोनों के लाभ उठाने पर सकती शुरू कर दी है। इसका असर भी साफ दिख रहा है। पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक पहली किस्त उठाने वालों में महिलाओं की सं या 25.3 फीसद थी, जो 9वीं तक आते-आते 21.3 फीसद रह गई। बता दें इस योजना के तहत केंद्र सरकार सालाना 6000 रुपये की राशि किसानों के खातों में 2000-2000 रुपये के तीन किस्तों में डायरेक्ट ट्रांसफर करती है। दरअसल पीएम किसान स मान निधि योजना किसान परिवारों के लिए है न कि व्यक्तिगत। परिवार का आशय पति-पत्नी और दो नाबालिग बच्चों से है। स्कीम के नियमों के मुताबिक पीएम किसान का पैसा किसान परिवार को मिलता है यानी परिवार के किसी एक सदस्य के खाते में 6000 रुपये सालाना 2000-2000 की तीन किस्तों में डायरेक्ट बैंक खाते में आते हैं। अगर पति-पत्नी एक साथ रहते हैं और भले ही दोनों के नाम पर अलग-अलग कृषियोग्य जमीन है, इनमें से केवल एक ही को योजना का लाभ मिलेगा।

डिजिटल इंडिया ने रणनीतिक लाभ पैदा करने में किया योगदान: चंद्रशेखर

नईदिल्ली । इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक सप्ताह तक चलने वाले आजादी का डिजिटल महोत्सव का उद्घाटन करते हुये आज कहा कि डिजिटल इंडिया ने डिजिटल बुनियादी ढांचे तथा सेवाओं के लचीलेपन को साबित कर दिया है और भारत महामारी के बाद की दुनिया में अधिक आत्मविश्वास वाला और अधिक आशावादी राष्ट्र बनकर उभरा है। श्री चंद्रशेखर ने कहा कि 2021 एक महत्वपूर्ण वर्ष है। डिजिटल इंडिया ने लोगों के जीवन को बदलने, डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने और देश के लिए रणनीतिक लाभ पैदा करने में काफी योगदान किया है। भविष्य में प्रौद्योगिकी की बढ़ती तीव्रता और नागरिकों की आकांक्षाओं को स्वीकार करते हुए उन्होंने छह मोर्चों, अर्थात सभी के लिए कनेक्टिविटी, सरकारी सेवाओं और उत्पादों का स्मार्ट आर्किटेक्चर संचालित डिजिटलीकरण, भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था, वैश्विक मानक कानून, नेतृत्व प्रौद्योगिकी विशेषकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उन्नत प्रौद्योगिकी का नेतृत्व और 5जी एवं व्यापक-आधारित कौशल और प्रतिभा पूल पर आवश्यक कार्यों का सार प्रस्तुत किया।

बिटकाइन को करेंसी के रूप में मान्यता देने का कोई प्रस्ताव नहीं : सीतारमण

बिटकाइन को 2008 में प्रोग्रामरों के एक अज्ञात समूह द्वारा एक क्रिप्टोकरेंसी के साथ-साथ एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के रूप में पेश किया था

नईदिल्ली । (एजेंसी)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में अपने जवाब में कहा कि सरकार के पास देश में बिटक्वाइन को मुद्रा के रूप में मान्यता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने सदन को यह भी बताया कि सरकार बिटक्वाइन लेनदेन पर डेटा एकत्र नहीं करती है। क्या सरकार के पास देश में बिटक्वाइन को मुद्रा के रूप में मान्यता देने का कोई प्रस्ताव है के प्रश्न पर वित्त मंत्री ने कहा नहीं, सर।

बता दें बिटक्वाइन एक डिजिटल मुद्रा है जो लोगों को बैंकों, क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं या अन्य तीसरे पक्षों को शामिल किए बिना सामान और सेवाओं को खरीदने और पैसे का आदान-प्रदान करने की अनुमति देता है। इसे 2008 में प्रोग्रामरों के एक अज्ञात समूह द्वारा एक क्रिप्टोकरेंसी

के साथ-साथ एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के रूप में पेश किया गया था। यह कथित तौर पर पहली विकेन्द्रीकृत डिजिटल मुद्रा है जहां पीयर-टू-पीयर लेनदेन बिना किसी मध्यस्थ के होते हैं। इस बीच, सरकार की योजना संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र में आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक 2021 की क्रिप्टोक्यूरेंसी और विनियमन पेश करने की है।

आरबीआई द्वारा आधिकारिक डिजिटल मुद्रा की अनुमति

विधेयक में अंतर्निहित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए कुछ निजी क्रिप्टोकरेंसी को छोड़कर सभी पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया है, जबकि आरबीआई द्वारा आधिकारिक डिजिटल मुद्रा की अनुमति दी गई है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में, सीतारमण ने कहा, मंत्रालयों और विभागों ने चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-सितंबर अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय के रूप में 2.29 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं। यह 2021-22 के 5.54 लाख करोड़ रुपये के बजट अनुमान (बीई) का 41 फीसदी है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान वास्तविक व्यय वित्त वर्ष 2020-21 में इसी व्यय की तुलना में लगभग 38 प्रतिशत अधिक है।

बुनियादी ढांचे के निर्माण और उन्नयन के लिए पूंजीगत व्यय में तेजी के प्रयास

अर्थव्यवस्था में बुनियादी ढांचे के निर्माण और उन्नयन के लिए पूंजीगत व्यय में तेजी लाने के लिए, भारत सरकार ने देश भर में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए 2020-2025 की अवधि के दौरान 111 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित बुनियादी ढांचे के निवेश के साथ राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन (एनआईपी) शुरू की थी।

कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रान का प्रभाव

एलपीजी सिलेंडर से लेकर पेट्रोल व डीजल तक हो सकते हैं सस्ते

नई दिल्ली । पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों से आम लोगों को एक और बड़ी रहने मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम पांच रुपये प्रति लीटर तक कम हो सकते हैं। ऊर्जा विशेषज्ञों ने वैश्विक हालत के चलते कच्चे तेल के दाम में आई बड़ी गिरावट के बाद ये अनुमान लगाए हैं। हर महीने की 1 तारीख को कमर्शियल और घरेलू सिलेंडरों के नए रेट जारी किए जाते हैं। इस बार 1 दिसंबर को होने वाली समीक्षा में पूरी संभावना है कि सिलेंडर के घटेंगे। ऐसा इसलिए कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई हैं।

आईआईएफएल सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसीडेंट (करेंसी व एनर्जी रिसर्च) अनुज गुप्ता ने हिन्दुस्तान को बताया कि कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ओमिक्रान के डेल्टा से ज्यादा संक्रामक होने की खबर से पुरी दुनिया एहतियात बरत रही है। इसके चलते दुनियाभर के देश एक बार फिर से हवाई यात्रा पर प्रतिबंध समेत लॉकडाउन का सहारा ले रहे हैं। इसके चलते शुक्रवार को कच्चे तेल का दाम एक दिन में करीब 12 फीसदी टूटकर 72 डॉलर प्रति बैरल तक लुढ़क गया। अगर आने वाले दिनों में ओमिक्रान से खतरा बढ़ता है तो दुनियाभर के देश स ती बढ़ाएंगे। ये कच्चे तेल की मांग को कम करने का काम करेगा। वहीं, वैश्विक दवाब के बाद 2 दिसंबर को होने वाली ओपेक देशों की बैठक में कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। ऐसे कच्चे तेल की आपूर्ति बढ़ने और मांग कम होने से कीमत में कमी आना तय है।

टॉप-10 अरबपतियों की कमाई में ओमिक्रान ने लगाई सेंध

पिछले हफ्ते दिया 28,44,58,50,00,000 रुपए का झटका

नई दिल्ली। (एजेंसी)। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रान की दहशत से दुनियाभर के शेयर बाजार धड़ाम हो गए। वायरस के इस नए स्वरूप से न केवल बाजार बीमार हो गए बल्कि दुनिया टॉप-10 अरबपतियों की संपत्ति में करीब 38 अरब डॉलर की कमी आ गई।

ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के ताजा आंकड़ों के मुताबिक एलन मस्क, जेफ बेजोस, बर्नार्ड आर्नाल्ट, जुकरबर्ग, बिलगेट्स समेत सभी टॉप 10 रईसों की नेटवर्थ में 38 बिलियन डॉलर (28,44,58, 50,00,000 रुपये) की सेंध लग गई है। दक्षिण अफ्रीका, चीन, बोत्सवाना, यूके, ब्राजील, इज़राइल, बांग्लादेश, मॉरीशस, न्यूजीलैंड, जि बाब्वे, सिंगापुर, और हांगकांग सहित यूरोप के देशों में वायरस के प्रभाव की वजह से दुनिया अलर्ट मोड में है। पिछले ह ते एलन मस्क को 8.38 अरब डॉलर की चोट पहुंची। वहीं, जेफ बेजोस को 3.90 अरब डॉलर तो बर्नार्ड आर्नाल्ट को 8.26 अरब डॉलर की। बिलगेट्स की संपत्ति में 2.68 अरब डॉलर की कमी आई है। लैरीपेज की संपत्ति में जहां 3.14 अरब डॉलर की तो मार्क जुकरबर्ग की संपत्ति में 2.93 अरब डॉलर की सेंध लगी है। सर्गी ब्रिन, स्टीव वॉल्मर, लैरी एलिशन और वॉरेन बफेट को भी एक से 3 अरब डॉलर तक की चोट पहुंची है।

बाजार में लौटी तेजी, सेंसेक्स और निफ्टी में मामूली बढ़त

आईटी, टेक, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऊर्जा समूह में लिवाली से बाजार को मिला बल

मुंबई । कोरोना के नये वैरिएंट ओमिक्रान से डरे निवेशकों की भारी बिकवाली से पिछले सप्ताह भूचाल देख चुके घरेलू शेयर बाजार में आज आईटी, टेक, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ऊर्जा समूह में हुई लिवाली से तेजी लौट आई लेकिन बिकवाली का दबाव बरकरार रहने से सेंसेक्स और निफ्टी मामूली बढ़त के साथ बंद हुए।

बीएसई का तीस शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 153.43 अंक की तेजी लेकर 57,260.58 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 27.50 अंक की मामूली बढ़त के साथ 17,053.95 अंक पर रहा। दिग्गज कंपनियों के विपरीत छोटी और मझौली कंपनियों में हुई करीब दो प्रतिशत तक गिरावट ने शेयर बाजार को और चढ़ने से रोक दिया। मिडकैप 230.72 अंक लुढ़ककर 24,615.79 अंक और स्मॉलकैप 532.48 अंक का गोता लगाकर 27,538.93 अंक पर रहा। इस दौरान बीएसई में कुल 3575 कंपनियों के शेयरों में कारोबार हुआ, जिनमें से 966 में लिवाली जबकि 2435 में बिकवाली हुई वहीं 174 के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसी तरह एनएसई में 15 कंपनियों के शेयर हरे जबकि 35 लाल निशान पर रहे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलाजुला रुख रहा। ब्रिटेन का एफटीएसई 0.83 और जर्मनी का डैक्स 0.38 प्रतिशत चढ़ गया जबकि जापान का निक्केई 1.63, हांगकांग का हैंगसैंग 0.95 और चीन का शंघाई कंपोजिट 0.04 प्रतिशत गिर गया।

बीएसई में ऊर्जा, आईटी, दूरसंचार, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, बैंकिंग और टेक समूह की 0.67 प्रतिशत की तेजी को छोड़कर शेष समूह गिरावट पर रहे। इस दौरान यूटिलिटीज समूह के शेयरों ने सबसे अधिक 2.61 प्रतिशत का गोता लगाया। इनके अलावा बेसिक मैटेरियल्स 0.80, सीडीजीएस 1.00, एफएमसीजी 0.78, हेल्थकेयर 0.59, इंडस्ट्रियल्स 1.08, कैपिटल गुड्स 0.75, तेल एवं गैस 1.51, पावर 1.97 और रियल्टी 1.98 प्रतिशत की गिरावट पर रहे।

बाजार समीक्षा सिल्वर ईटीएफ से निवेशक तरलता पूर्वक कर सकेंगे निवेश

चांदी ईटीएफ से विविधीकरण में मिलेगी मदद

इंदौर। सिल्वर (चांदी) एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) के नियम आने के साथ अब निवेशक चांदी में अधिक तरलता पूर्वक निवेश कर सकेंगे और इससे उन्हें पोर्टफोलियो के विविधीकरण में मदद मिलेगी। उल्लेखनीय है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कुछ दिन पहले ही चांदी ईटीएफ के लिए परिचालन मानदंड जारी किए हैं। इसके तहत ऐसी निवेश योजना को चांदी और इससे संबद्ध उत्पादों में कम से कम 95 प्रतिशत का निवेश करना होगा। ये मानदंड 9 दिसंबर21 से प्रभावी होंगे।

वर्तमान में म्यूचुअल फंड इकाइयों को गोल्ड ईटीएफपेश करने की ही अनुमति है, लेकिन नए प्रावधान आने के बाद सिल्वर ईटीएफ का रास्ता भी खुल गया है। नियो के रणनीति प्रमुख स्वप्निल ने कहा अब लोग सिल्वर ईटीएफ में निवेश करके चांदी भी रख सकेंगे। चूंकि यह एक उच्च विनियमन वाला उत्पाद है, इसलिए निवेशक इसकी शुद्धता के बारे में निश्चित होंगे। बाजार से चांदी लेने पर उन्हें ऐसी निश्चिंतता नहीं मिलती है। महिलाओं के वित्तीय मंच एलएक्सएमई की संस्थापक प्रीति राठी गुप्ता ने कहा अब निवेशक चांदी में निवेश के पारंपरिक तरीकों के मुकाबले अधिक तरलता से निवेश कर सकेंगे, क्योंकि सोन-चांदी को भी बहुमूल्य धातु श्रेणी में रखा जाता है। नियमों के तहत सिल्वर ईटीएफयोजना में चांदी की कीमत लंदन बुलियन मार्केट एसो. के दैनिक हाजिर मूल्य आधार पर बेंचमार्क किया जाएगा। ऐसे ईटीएफ का शुद्ध संपत्ति मूल्य (एनएवी) एएमसी की वेबसाइट पर डाला जाएगा। इस से निवेशकों को वास्तविक मूल्य निर्धारण मिलेगा। सेबी ने एलबीएमए के माध्यम से एएमसी के लिए खुद 99.9 प्रतिशत शुद्ध चांदी छड़ें रखने की प्रथा है। इससे निवेशकों को शुद्धता, जोखिम, भंडारण, चिंता बिना चांदी निवेश की अनुमति मिलेगी।

ओमीक्रोन चिंता से रुपया 23 पैसे गिरकर 75.12 पर

मुंबई। कोविड-19 के नये स्वरूप ओमीक्रोन को लेकर निवेशकों द्वारा सतर्कता का रुख अख्तियार किया जा रहा है। सोमवार को विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 23 पैसे गिरकर 75.12 पर बंद हुआ। विनिमय बाजार में रुपया 74.84 पर खुला। कारोबार के दौरान यह 74.82 से 75.16 के दायरे में दिखाई दिया। गत शुक्रवार को रुपया 37 पैसे की गिरकर एक माह के निचले स्तर 74.89 पर बंद हुआ था। यूरोप में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों और दक्षिण अफ्रीका में नये स्वरूप के सामने आने के बीच निवेशकों में लॉकडाउन को लेकर चिंता फिर उभरने लगी है।

सोयाबीन वायदे में 6 प्रतिशत मंदी का सर्किट, तेलों में मंदी

इंदौर। सोमवार को सोयाबीन वायदे में 6 पीसदी मंदी का सर्किट देखा गया। इससे हाजिर कीमतों पर भी दबाव नजर आया। सोयाबीन आवक प्रदेश में 3 लाख महाराष्ट्र में 2.50 लाख बोरी सहित समुचे देश में 6.10 लाख बोरी हुई। एनसीडीईएक्स पर सोयाबीन वायदा दिसंबर 402 रु गिरकर 6306, जनवरी 6302 रु था। देश में सरसों की आवक 1.50 लाख बोरी बताई गई। जयपुर में तेल कंडीशन आधारित सरसों का दाम घटकर 8175 रु का रह गया। प्लांटों सौदो में सोयाबीन के दाम अवि 6400, धानुका 6500, कोरोनेशन 6300, एमएस नीमच 6500, सांवरिया 6400, खंडवा 6400, प्रेस्टीज 6450, अंबूजा 6325, अंबिका 6450 रु क्विंटल थे। खाद्य तेल प्रति 10 किलो सोया रिफाइंड 1235-1240, साल्वेंट 1180-1185, मुंबई रिफा. 1235, मूंगफली तेल 1340-1350, मुंबई 1335, गुजरात 1300, कॉटन तेल 1180-1185,, पाम तेल मुंबई 1190, इंदौर पाम तेल 1265 रु थे। **कपास्या खली मंदी- दाम घटकर** प्रति 60 किलो के सौदो में इंदौर 1875, देवास-उज्जैन 1875-188, खंडवा-बुरहानपुर 1850-1855 एवं अकोला 2800 रु क्विंटल थी।

गेहूं की बुआई में बढ़त से कीमतों पर दबाव

इंदौर। कृषि विभाग के अनुसार देश में गेहूं की बुआई गत वर्ष के 133.84 लाख की तुलना में बढ़कर 138.35 लाख हैक्टेयर हो चुकी है। इससे गेहूं के बेहतर उत्पादन का अनुमान है। इसके चलते स्टॉक वालों की बिकवाली बढ़ने से कीमतों पर दबाव देखने को मिल रहा है। मोटे अनाज की बुआई पिछड़ने से मक्का के दाम मजबूत थे। सोमवार को मिल डिलीवरी सौदो में गेहूं इंदौर, देवास, पीथमपुर, 2080-2100, पुणे 2320, अहमदनगर 2280, कोल्हापुर-सांगली 2350, हैदराबाद 2400, बैग्लुरु 2500, मैसूर 2550 रु क्विंटल थे। मक्का डिलीवरी इंदौर 1670, सारसा 1850, अहमदाबाद 1880, धुलिया 1830, घाटाबिल्लोद1750 रु थी।

चना घटकर 5000 रु बिका

इंदौर। नेफेड की बिकवाली के बाद से ही चने के भाव में मंदी का दौर देखने को मिल रहा है। सोमवार को स्थानीय मंडी में चना कांटा घटकर 5000 रु रह गया। डॉलर चने में भी मांग कम होने से कीमतों पर दबाव दिखाई दिया। उड़द के दाम मजबूत थे। मंडी में डॉलर चना आवक करीब 1800 बोरी की दर्ज हुई, दाम घटकर मंडी में 7500 से 8600 निर्यात सौदो में 42-44 काउंट 8800,58-60 काउंट 8350, चना 5000, विशाल 4800, मसूर 7200-7225, उड़द 7100-7400, एवरेज 5000-6600, मूंग 7000-7200, एवरेज 5500-6500, तुवर 5200-5600, महाराष्ट्र 6000-6100, कर्नाटक 6200-6300 रु क्विंटल थी।

दाल-चावल भाव

दालें- चना दाल 5750-6350, तुवर दाल 8450-9550, मसूर दाल 8400-9500, मूंग दाल 7900-8200, मोगर 8500-8800, उडद दाल 8400-8700, मोगर 9800-10300 रु।

चावल- दयाल दास अजित कुमार छावनी के अनुसार बासमती (921) 9000-9500, तिबार 7500-8000, दुबार 6500-7000, मिनी दुबार 6000-6500, मोगरा 3000-5500, सैला 5000-7500, कालीमूंछ डिनरकिंग 7000, राजभोग 6000, दूबराज 3500-4000, परमल 2400-2600 हंसा सैला 2400-2550 हंसा सफेद 2300-2400 पोहा 3200-3600 रु।

महाराष्ट्र में चीनी रिकवरी बढ़ी

मुंबई। महाराष्ट्र में चीनी मिलें तेजी गति से चल रही है। राज्य में मिलों ने गन्ना पेराई में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। चीनी आयुक्तालय के मुताबिक, महाराष्ट्र में कुल 157 चीनी मिलों ने पेराई शुरू कर दी है। जिसमे 75 सहकारी एवं 82 निजी चीनी मिलें है, और गत दिवस तक 195.86 लाख टन गन्ना पेराई द्वारा अब तक 176.58 लाख क्विंटल चीनी उत्पादन किया गया है। राज्य में फिलहाल औसत चीनी रिकवरी बढ़कर 9 प्रतिशत के पार हो चुकी है। चीनी मिलों ने औसत चीनी रिकवरी 9.02 प्रतिशत दर्ज की है।

महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सोलापुर विभाग की 37 चीनी मिलों ने पेराई चालू की है। आयुक्तालय के मुताबिक, 27 नवंबर तक सोलापुर विभाग में46.51 लाख टन गन्ना पेराई से 38.06 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया गया है। कोल्हापुर विभाग में चीनी रिकवरी 10 फीसद के पार हो चुकी है और राज्य में सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन भी कोल्हापुर विभाग में हुआ है। कोल्हापुर में फिलहाल 51.55 लाख टन गन्ना पेराई से 52.80 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया गया है।

अंचल की मंडी

नीमच: मूंगफली और मैथी में भाव का रुख सुधारात्मक, मक्का, सोयाबीन, रायडा मंदे

नीमच (शंकर बंसल)- सोमवार को मिले जुले रुख के बीच नीमच मंडी में मूंगफली और मैथी के दाम मजबूत बताए जा रहे थे,जबकि मक्का, सोयाबीन और रायडा के दाम मंदे रहे। भाव- गेहूं 2050-2241, जौं 2250-2400, मक्का 1575-1730, सोयाबीन 5750-6650, रायडा 7300-7500, अलसी 9000-9450, तारामीरा 00, मूंगफली 3700-5580, डॉलर चना 6500-8300, चना 4200-4500, मसूर 5500-6500, उड़द 3500-7100, मैथी 6200-7000, धनिया 7800-8200, अजवाइन 9000-13000, इसबगोल 11000-13400, कलौंजी 00, तिल्ली 9000-11600, असगंध 12000-29000, पोस्ता 90000-180000, लहसुन 2500-6200, ऊंटी 00, प्याज 300-1611 रुपए। **मंदसौर-** मंडी में 37817 बोरी आवक दर्ज हुई। भाव- मक्का 1680-1964, उड़द 3000-6900, सोयाबीन 5500-6420, गेहूं 1950-2196, चना 3700-4501, मसूर 4000-6500, धनिया 5910-7420, लहसुन 1201-9500, मैथी 5820-7040, अलसी 8000-9800, सरसों 6871-7501, तारामीरा 5940-6000, इसबगोल 11200-12770, प्याज 300-1800, कलौंजी 7000-17000, तुलसी बीज 00, डॉलर चना 4200-8400, तिल्ली 8650-10700, मटर 3800-4970, असालिया 5290-6094 रु। **निमरानी-** स्थानीय मंडी में सोमवार को गेहूं 1250 बोरी आवक हुआ, जो 1925-2040 रु बिका। **खेतिया-** स्थानीय मंडी में सोमवार को कपास 186 वाहन, 9 बैलगाड़ी आवक हुई जो 7750-8250 रु बिका। **खंडवा-** स्थानीय मंडी में सोमवार को कपास 374 वाहन, 6 बैलगाड़ी आवक के बीच भाव- कपास 6000-8571, गेहूं 1800-2045, सोयाबीन 4000-8451, तुवर 00, मक्का 1150-1646, चना 3600-4422, उड़द 3100-3890, मूंग 3500 रु। **खरगोन-** खरगोन मंडी में 15207 क्विंटल आवक हुई। कपास 675 वाहन एवं 194 बैलगाड़ी की आवक हुई। भाव- कपास 4000-8490, गेहूं 1790-2096, चना 3900-4444, ज्वार 00, मक्का 1451-1635, सोयाबीन 5896-6288 रु। **महू-** स्थानीय मंडी में सोमवार को सोयाबीन 4068-6501, चना 4218-4800, चना बिटकी 4306-4870, डॉलर चना 5700-8507, गेहूं 1825-2116, मक्का 1400-1608, बटला 00 रु। **धामनोद-** स्थानीय मंडी में सोमवार को कपास 411 वाहन, 51 बैलगाड़ी आया। भाव- कपास 4405-8655, गेहूं 1908-2025, मक्का 1400-1625 सोयाबीन 2500-6250, मौसमी चना 4350 रुपए। **बुरहानपुर-** स्थानीय मंडी में सोम वार को नीलामी के दौरान विभिन्न जिंसों के दाम इस प्रकार थे। गेहूं 1875-2175, ज्वार 1248-2429, मक्का 1391-1703, सोयाबीन 5850-6141, चना 00 रु। **भीकनगांव-** स्थानीय मंडी में सोमवार को कपास की आवक 240 वाहन, 158 बैलगाड़ी की दर्ज हुई। नीलामी में भाव इस प्रकार थे-कपास 4000-8651, गेहूं 1967-2009, सोयाबीन 4500-7820, मक्का 1440-1715 रुपए। **बड़नगर-** सोमवार को मंडी में 18788 बोरी की आवक हुई। जिसमें गेहूं लोकवन 456, गेहूं पूर्णा 294, चना इटालियन 56, डॉलर चना 511, विशाल चना 69, मसूर 9, उड़द 15, बटला 224, मैथी दाना 13, लहसुन 38 व सोयाबीन 17103 बोरी शामिल थी। नीलामी के दौरान विभिन्न जिंसों के दाम इस प्रकार थे- गेहूं लोकवन 1692-2080, गेहूं पूर्णा 1784-2139, चना इटालियन 4210- 4950, चना विशाल 4110-4576, चना डॉलर 6510-8551, मसूर 5040-5550, उड़द 2080-3830, बटला 4000-5230, सोयाबीन 3514-8111, मैथी 6350, लहसुन 1520-3140 रु क्विंटल।

पंजाब में गन्ने पर कीट प्रकोप बढ़ने से फसल हुई प्रभावित

चंडीगढ। पंजाब के गन्ने के मूल्य बढ़ने की किसानों की खुशी कम हो गई है, क्योंकि फसल पर टॉप बोरर के हमले से गन्ना प्रभावित हो रहा है। राज्य में गन्ना पेराई का सीजन आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है, और किसानों ने फसल की कटाई भी शुरू की है।

खबर के मुताबिक दसूया, टांडा और गुरदासपुर के कुछ हिस्सों में किसान फसल की कम उपज से किसान निराश हैं। वर्ष की शुरुआत में 448 एकड़ में लाल सड़न का हमला हुआ था। इससे गुरदासपुर, होशियारपुर, अमृतसर, जालंधर, पठानकोट जिलों और लुधियाना के कुछ हिस्सों में गन्ना खेती प्रभावित हुई। दोआबा किसान समिति के अध्यक्ष और गन्ना उत्पादक जंगवीर सिंह चौहान ने कहा यदि पहले गन्ने की उपज 300 क्विंटल थी, तो अब यह टॉप बोरर अटैक के कारण 240 से 250 क्विंटल रह गई है। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि भविष्य में कीटों के हमले कम से कम हों। जिसके लिए वे गन्ने के बीज को कीट-प्रतिरोधी किस्मों से बदल रहे हैं। इस वर्ष पंजाब में गन्ने का मूल्य बढ़ाकर 360 रु क्विंटल कर दिया है। इस बढ़ोतरी की घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टेन अमरिंदर सिंह ने की थी। हालांकि, राज्य में सात निजी चीनी मिल मालिकों ने बढ़ी हुई कीमत पर भुगतान से इनकार कर दिया एवं राज्य सरकार से बढ़ी कीमत का भुगतान करने को कहा। तब तय हुआ कि बढ़ी हुई कीमत का 70 फीसदी राज्य वहन करेगा।

सोना-चांदी में कीमतों का रुख सुधारात्मक

इंदौर। डॉलर के मुकाबले रुपया गिरने से भारतीय बाजारों में सोना-चांदी का रुख सुधारात्मक था। कॉमेक्स पर सोना ऊंचे में 1800.3, नीचे में 1788.8 डॉलर, चांदी ऊंचे में 2351, नीचे में 2305 सेंट प्रति औंस थी। **इंदौर सराफा-** बाजार में सोना 50 रु बढ़कर केश में 49500-49550, आरटीजीएस में 49450 रु प्रति 10 ग्राम व चांदी 150 रु किलो बढ़कर केश में 64550-64650, आरटीजीएस 64400 रु किलो थी। **रतलाम सराफा** आरटीजीएस सोना 49500 रु और चांदी 64100 रु किलो के भाव थी। **उज्जैन सराफा-** में सोना 49500 रु प्रति 10 ग्राम , चांदी 64100 रु प्रति किलो थी। **दिल्ली सराफा-** सोना 242 रु बढ़कर 47242 रु व चांदी 543 रु बढ़कर 62248 रु थी।

वैश्विक सराफा

विवरण	सोना	चांदी
ऊंचे में	1800.30	23.51
नीचे में	1788.80	23.05
रनिंग में	1789.50	23.15

नारियल एवं बादाम में गिरावट

इंदौर। सोमवार को थोक किराना बाजार में ग्राहकी का दायरा अपेक्षा से कमजोर था। इसके चलते नारियल में गिरावट देखी गई। बादाम में ठंड की सीजनल खरीदी कम होने से दाम 10-12 रुपए किलो मंदे बताए गए। शकर में मिलों पर बिकवाली का दबाव होने से भाव नीचे स्तर पर थे। खोपराबूरा में तेजी की धारणा है।

शकर 3540-3570, सुपर 3580-3600, एम 3700, गुड़ भैली 3300-3400, कटोरा 3600-3700, लड्डू 3900-4000, बरफी 4300-4400, कालीमिर्च कालामोती 565, दीपक 579, गणेश 590 मटरदाना 608, जीरा पंजा 179, खुशबू 181, सुपर 185-205 हल्दी सांगली 156-158, निजामाबाद 110-121, पीसी हल्दी प्रति 15 किलो 1750-1850, नारियल प्रति बोरी 120 भर्ती 1550-1600, 160 भर्ती 1600-1650, 200 भर्ती 1650-1700, 250 भर्ती 1650-1700, खोपरा गोला 208-230, खोपराबूरा प्रति 15 किलो 2650-4300, साबूदाना 4200-4600, वरलक्ष्मी 4850, ग्लास 5400, वरलक्ष्मी 1 किलो पैक में 5600, सौंफ 150-205, हल्की 105-115, लौंग 670-740, दालचीनी 265-275, जायफल 750-800, जावत्री 1900-2000, शाहजीरा 300-525 बड़ी इलायची 751-800, तरबूज मगज 280-

290, चारोली 1100-1300, इलायची एक्स्ट्रा बोल्ड 1800-1850, बोल्ड 1650-1700 मध्यम 1550-1600, मिनी 1400-1500, पानपट्टी 1300-1400, पोस्ता 1250-1170, टिनोपाल 1850काजू (240) 780-800, (320) 700-715, डब्ल्यू वन (300) 680-690, एस एस डब्ल्यू 640-655, जेएच 620-630, काजू टुकड़ी 675-700, बादाम इनडिपेंटेड 550, अमेरिकी 650-660, आस्ट्रेलियन 690-700, टांच 500-525, किशमिश कंधारी 375-550, इंडियन 210-240, मखाना 675-900, पिस्ता 1250-1325, नमकीन 850-950, चारोली 1100-1300। **आटा-मैदा** (50 किलो) आटा 1230, मैदा 1240, रवा 1270, बेसन 3375-3400 रु।

क्या 'ओमिक्रॉन' के चलते भारत के दक्षिण अफ्रीका रवाना होने में होगी देरी? बीसीसीआई कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने दिया जवाब

नई दिल्ली (एजेंसी)।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने मंगलवार को कहा कि भारत का दक्षिण अफ्रीका दौरा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा, बशर्ते वहां कोविड-19 का नया वैरिएंट मिलने के बाद स्थिति खराब न हो। भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ मुंबई में दूसरा और आखिरी टेस्ट खेलना है, जिसके बाद टीम वहां से आठ या नौ दिसंबर को चार्टर्ड विमान से जोहानिसबर्ग के लिए रवाना होगी। धूमल ने भरोसा जताया कि दक्षिण अफ्रीका द्वारा तैयार जैविक रूप से सुरक्षित माहौल में खिलाड़ी सुरक्षित रहेंगे। पहला टेस्ट जोहानिसबर्ग में 17 दिसंबर से खेला जाएगा।

धूमल ने पीटीआई से कहा, 'हम उनके साथ खड़े हैं। बात सिर्फ इतनी है कि हम खिलाड़ियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे। फिलहाल हमारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जोहानिसबर्ग के लिए चार्टर्ड फ्लाइट की योजना है और खिलाड़ी जैविक रूप से सुरक्षित माहौल में रहेंगे।' खतरे से निपटने के लिए दक्षिण अफ्रीका के अंदर स्थलों के संभावित बदलाव पर धूमल ने कहा, 'हम लगातार क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (सीएसए) के अधिकारियों के संपर्क में हैं। सीरीज को कोई नुकसान नहीं हो उसके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे, लेकिन अगर स्थिति खराब होती है और इससे हमारे खिलाड़ियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य से समझौता होता है तो हम देखेंगे।'

उन्होंने कहा, 'अंत में हम भारत सरकार के आदेश का पालन करेंगे।' दुनिया भर के कई देशों ने पहले ही कड़े कदम उठाते हुए दक्षिण अफ्रीका से यात्रा पर बैन लगा दिया है, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया है। भारत सरकार के संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, दक्षिण अफ्रीका 'जोखिम' वाले देशों की लिस्ट में शामिल है। भारत ए टीम भी दक्षिण अफ्रीका में सीरीज खेलती रहेगी।दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रालय ने भी भारतीय सीनियर क्रिकेट टीम के अगले महीने सीरीज के लिए वहां पहुंचने पर जैविक रूप से पूरी तरह सुरक्षित वातावरण तैयार करने का वादा किया है। भारत दक्षिण अफ्रीका दौरे पर तीन टेस्ट, तीन वनडे और चार टी-20 इंटरनेशनल मुकाबले खेलेगा।

एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम कोरिया रवाना

बेंगलुरु (एजेंसी)।

एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम मंगलवार को कोरिया के लिए रवाना हो गई।

यह टूर्नामेंट 5 से 12 दिसंबर के बीच खेला जाएगा, जिसमें भारत का मुकाबला चीन, कोरिया, जापान, थाईलैंड और मलेशिया से होगा। भारत 5 दिसंबर को थाईलैंड के साथ पहला मैच, 6 दिसंबर को मलेशिया और 8 दिसंबर को मेजबान और गत चैंपियन कोरिया के खिलाफ मैच खेलेगा। इसके अलावा, भारत 9 दिसंबर को चीन और 11 दिसंबर को जापान से खेलेगा। 12 दिसंबर को फाइनल, पूल के टॉपर और दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम के बीच होगा। भारत की महिला हॉकी कप्तान सविता ने टीम के रवाना होने से पहले उत्साह व्यक्त करते हुए कहा, निश्चित रूप से पूरी टीम उत्साहित है। ओलंपिक के बाद यह हमारा पहला टूर्नामेंट है और हमारी जिम्मेदारी है कि यहां अच्छा प्रदर्शन करें। हमारे पास काफी महिला युवा खिलाड़ी हैं जो टीम का हिस्सा हैं, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डेब्यू करेंगे, उनसे भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी।

मुझे प्रेरित करने के लिए धन्यवाद भज्जी पा : अश्विन

कानपुर (एजेंसी)।

भारत के स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने पूर्व दिग्गज खिलाड़ी हरभजन सिंह को ऑफ स्पिन गेंदबाजी करने के लिए प्रेरित करने को लेकर उनका धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भज्जी के अद्भुत स्पेल को देखने के बाद ही मैंने गेंदबाजी करनी शुरू की थी।

सोमवार को अश्विन ने हरभजन के 417 विकेटों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, उन्होंने यहां ग्रीन पार्क में न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरुआती टेस्ट के अंतिम दिन 419 टेस्ट क्रिकेट लेकर भारत के तीसरे सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए, लेकिन यह मैच दोनों टीमों के बीच बेनतीजा रहा। 28 नवंबर को 35 साल के खिलाड़ी ने विल यंग को 4 दिन पर आउट करने के बाद हरभजन के 417 विकेटों की बराबरी की थी। अश्विन ने न्यूजीलैंड की दूसरी पारी में टॉम लैथम को आउट करके टेस्ट में हरभजन के 417 विकेटों को पीछे छोड़ दिया। अश्विन ने मंगलवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में कहा, यह मेरे लिए एक अद्भुत मुकाम है। हरभजन सिंह, जब उन्होंने 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक बेहतर स्पेल में गेंदबाजी की थी, तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उनको देखकर कभी एक ऑफ स्पिनर भी बनूंगा। उनसे प्रेरित होकर, मैंने गेंदबाजी शुरू की और इस वजह से मैं यहां हूं। मुझे प्रेरित करने के लिए भज्जी पा को धन्यवाद। अश्विन अब अनिल कुंबले (619) और कपिल देव (434) से पीछे हैं, जो भारत के सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने वालों की सूची में हैं। अश्विन 400 से ज्यादा विकेट लेने वाले चौथे भारतीय गेंदबाज हैं। सोमवार की उपलब्धि ने उन्हें पाकिस्तान के वसीम अकरम (414) को रिकॉर्ड तोड़ते हुए टेस्ट में 13वां सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज बना दिया। वह इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन के बाद सक्रिय क्रिकेटरों में तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, उन्होंने अब तक 524 और 632 विकेट लिए हैं। अश्विन, जिन्होंने नवंबर 2011 में नई दिल्ली में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था, उन्होंने 52.4 की स्ट्राइक रेट और 24.5 की औसत से विकेट लिए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के दूसरे सीजन के दौरान एक घटना को याद करते हुए, श्रेयस अय्यर, जिन्होंने डेब्यू पर शतक और अर्धशतक बनाकर ग्रीन पार्क को बल्ले से कमाल कर दिया, उन्होंने कहा कि अश्विन ने वानखेड़े में उनसे संपर्क किया था और फिर उनकी सलाह ली थी।अय्यर ने उस घटना को याद करते हुए कहा, आईपीएल के दूसरे सीजन में, मैं बॉल बॉय था और अश्विन मेरे पास आए और पूछे यहां हवा कौन सी दिशा से आती है, जरा बता दो। मैंने उस समय वानखेड़े में बहुत सारे मैच खेले थे। मैंने उनसे कहा, इधर से आती है, इस दिशा में समुद्र है, तो हवा उसी दिशा से आएगी। अश्विन ने टेस्ट डेब्यू पर शतक और अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय बनने के लिए अय्यर को बधाई देते हुए कहा, आपको (अय्यर) टेस्ट डेब्यू पर शतक और अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय बनने के लिए बधाई।

दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रालय ने दी गारंटी, टीम इंडिया को 'ओमिक्रॉन' वैरिएंट से कोई खतरा नहीं

जोहानिसबर्ग (एजेंसी)।

दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम अगले महीने यहां सीरीज खेलने पहुंचेगी तो उसके लिए कंप्लीट जैव सुरक्षित माहौल (बायो-बबल) तैयार किया जाएगा। मंत्रालय ने साथ ही कोविड-19 का नया वैरिएंट मिलने के बावजूद 'ए' टीम के दौरे से नहीं हटने के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की तारीफ भी की। भारत ए मंगलवार से ब्लोमफोंटेन में दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ दूसरा अनऑफिशियल टेस्ट खेलेगा। नया ओमिक्रॉन वैरिएंट मिलने के कारण वैश्विक चिंताओं के बावजूद भारतीय बोर्ड ने दक्षिण अफ्रीका में सीरीज जारी रखने का फैसला किया है।

भारतीय सीनियर टीम भी 17 दिसंबर से दक्षिण अफ्रीका में तीन टेस्ट खेलेगी, जिसके बाद इतने की वनडे इंटरनेशनल सीरीज और चार टी-20 इंटरनेशनल मुकाबले भी होंगे। विराट कोहली और उनकी टीम नौ दिसंबर को यहां पहुंचेगी, लेकिन देश में कोविड का ओमिक्रॉन वैरिएंट मिलने के बाद दौरे को लेकर कुछ चिंताएं हैं। इस नए वैरिएंट के सामने आने के बाद कई देशों ने यात्रा पाबंदियां लगाई हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं सहयोग विभाग (डर्को) जो देश का विदेश मंत्रालय है, ने कहा, 'भारतीय टीम के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए दक्षिण अफ्रीका सभी जरूरी एहतियाती कदम उठाएगा। दक्षिण अफ्रीका और भारत 'ए' टीम के अलावा दोनों नेशनल टीम के लिए पूर्ण रूप से जैव सुरक्षित माहौल तैयार किया जाएगा।'

मेसी के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज, सातवां बैलन डी ओर जीतो

पेरिस। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने अपने नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज किया, उन्होंने सातवीं बार बैलन डी ओर का पुरस्कार जीता है। 34 साल के मेसी ने पोलैंड के रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को पीछे छोड़ते हुए सोमवार को अपने लुइस सुआरेज के हाथों से ट्रॉफी हासिल की। अब पेरिस सेंट-जर्मेन (पीएसजी) स्ट्राइकर कट्टर प्रतिद्वंद्वी क्रिस्टियानो रोनाल्डो से दो जीत दूर है क्योंकि पांच बार के विजेता इस साल छठे स्थान पर रहे। पहली बार उन्हें 2010 के बाद से शीर्ष तीन में से वोट दिया गया था। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, पेरिस सेंट-जर्मेन ने 2009 से 2012 तक इस पुरस्कार पर अपना दबदबा कायम रखा और 2015 से 2019 में दो और जीते। पुरस्कार जीतने के बाद मेसी ने कहा, यह खिताब फिर से जीतकर अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा, दो साल पहले मैंने सोचा था कि यह आखिरी बार है। लोग मुझसे पूछने लगे थे कि मैं कब संन्यास लेने जा रहा हूं लेकिन अब मैं यहां पेरिस में हूं और बहुत खुश हूं।

गावस्कर ने न्यूजीलैंड की धीमी बल्लेबाजी को लेकर आलोचना की

नई दिल्ली। महान सुनील गावस्कर ने कानपुर टेस्ट की दूसरी पारी में न्यूजीलैंड की धीमी बल्लेबाजी को लेकर आलोचना की है। दूसरी पारी में टॉम लैथम और विलियम सोमरविले ने अपनी टीम के लिए एक शानदार शुरुआत करने के बाद, गावस्कर ने कहा कि मेहमान जीत के लिए नहीं खेल रहे थे, बल्कि वे ड्रॉ करने में लगे रहे।

भारत मैच में जीत से सिर्फ एक विकेट दूर था, लेकिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रचिन रवींद्र और एजाज पटेल ने 50 से अधिक गेंदें खेलकर कीवी टीम को टेस्ट ड्रॉ कराने में मदद की।

गावस्कर ने टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा, न्यूजीलैंड कानपुर में खेले गए मैच को ड्रॉ कराने में कामयाब रहा। पांचवें दिन की शुरुआत में उनकी धीमी बल्लेबाजी ने भारत को मैच में वापस ले आई और इसके बाद भारत ने दूसरे सत्र में विकेट हासिल करना शुरू कर दिया, जिससे वह पूरी तरह से ध्वस्त हो गए, लेकिन वह जीत के लिए नहीं, बल्कि ड्रॉ के लिए खेल रहे थे। गावस्कर का मानना है कि भारतीय कप्तान अजिंक्य रहाणे की अगुवाई वाली टीम के आक्रामक सोच को देखकर न्यूजीलैंड पूरी तरह से मैच को बचाने में लग गया।

पहली पारी में पिछड़ने के बावजूद पाकिस्तान ने बांग्लादेश को धोया, आबिद अली, शाहीन अफरीदी और हसन अली रहे जीत के हीरो

नई दिल्ली (एजेंसी)।

पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव में खेला गया पहला टेस्ट मैच आठ विकेट से अपने नाम कर लिया है। पाकिस्तान ने पहली पारी में पिछड़ने के बावजूद जबर्दस्त वापसी करते हुए यह मैच अपने नाम किया। इस मैच के दौरान ज्यादातर मौकों पर बांग्लादेश ड्राइविंग सीट पर रहा, लेकिन पाकिस्तान ने आखिरी दो दिन में मैच का रुख काफी कुछ अपनी तरफ मोड़ लिया। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और पहली पारी में 330 रन बना डाले। लिटन दान ने शानदार शतक जड़ा, जबकि पाकिस्तान की ओर से हसन अली ने पांच विकेट लिए।

जवाब में पाकिस्तान पहली पारी में 286 रन ही बना सका। आबिद अली ने 133 रनों की जोरदार पारी खेली, जबकि अब्दुल्ला शफीक ने 52 रनों का योगदान दिया। इसके अलावा कोई पाकिस्तान बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सका। बांग्लादेश की ओर से ताइजुल इस्लाम ने कुल सात विकेट चटकाए। पहली पारी के आधार पर मिली बढ़त का बांग्लादेश की टीम फायदा नहीं उठा सकी। दूसरी पारी में मेजबान टीम महज 157 रनों पर सिमट गई।

शाहीन शाह अफरीदी ने पाकिस्तान की ओर से दूसरी पारी में पांच विकेट झटके। लिटन दास ने दूसरी पारी में 59 रनों का योगदान दिया और दोनों पारियों में टीम की ओर से बेस्ट स्कोरर रहे है। 202 रनों का टारगेट पाकिस्तान ने दो विकेट गंवाकर ही हासिल कर लिया। आबिद और शफीक ने पहले विकेट के लिए 151 रनों की साझेदारी निभाई। शफीक 71 और आबिद 91 रन बनाकर आउट हुए। एक समय ऐसा लग रहा था कि आबिद दोनों पारियों में सैंकड़ा जड़ेंगे, लेकिन ताइजुल इस्लाम ने उन्हें आउट कर पाकिस्तान को दूसरा झटका दिया।

जोकोविच के पिता ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के आयोजकों से कहा, नोवाक शायद नहीं खेलेंगे

मेलबर्न। दुनिया के नंबर वन टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच 17 जनवरी से शुरू होने वाले ऑस्ट्रेलियन ओपन में शायद नहीं खेलेंगे। इसे लेकर उनके पिता को लगता है कि टूर्नामेंट के आयोजकों द्वारा बिना टीकाकरण रिपोर्ट खिलाड़ियों को अनुमति नहीं देने का निर्णय ब्लैकमेल के बराबर है। जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के आयोजकों को अपनी कोविड-19 टीकाकरण रिपोर्ट साझा नहीं की है, इस अनिश्चितता को देखते हुए लगता है कि अगले साल होने वाले टूर्नामेंट में शायद ही वह प्रतिस्पर्धा करेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन के निदेशक क्रेग टिली ने स्पष्ट रूप से कहा है कि केवल उन्हीं खिलाड़ियों को ही टूर्नामेंट में भाग लेने की अनुमति होगी जो कोविड टीकाकरण की रिपोर्ट साझा करेंगे। नौ बार के मौजूदा ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन जोकोविच ने अपने टीकाकरण की स्थिति का खुलासा करने से इनकार कर दिया है। हाल ही में टिली ने कहा था कि जोकोविच अपना वैक्सीनेशन स्टेटस किसी से शेयर नहीं किया है।

केएल राहुल और राशिद खान को आईपीएल 2022 से किया जाएगा बैन? पीबीकेएस और एसआरएच ने की बीसीसीआई से शिकायत!

नयी दिल्ली।(एजेंसी)।

आईपीएल 2022 को लेकर काफी बज बना हुआ है। भारत में सबसे ज्यादा पसंदीदा स्पोर्ट क्रिकेट है और आईपीएल को लेकर हमेशा से ही बज बना रहता है। दर्शक अपनी-अपनी टीमों को लीक के दौरान सपोर्ट करते हैं। आईपीएल 2022 रिटेंशन मंगलवार, 30 नवंबर को होने वाला है, जिसमें सभी आठ फैंचाइजी अपने खिलाड़ियों की सूची जमा करेंगे, जिसे टीम रिटेन करेगी। आईपीएल 2022 के लिए लखनऊ और अहमदाबाद में 2 नई टीमों को मैदान में जोड़ा गया है। हालाँकि विभिन्न मीडिया रिपोर्टें सामने आई हैं जिसमे यह दावा किया जा रहा है कि आईपीएल 2022 के रिटेंशन से पहले, दो खिलाड़ियों केएल राहुल और राशिद खान पर एक साल का प्रतिबंध लग सकता है। मेगा नीलामी से पहले रिपोर्टें में कहा गया है कि पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) के केएल राहुल और सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के राशिद खान से उनकी संबंधित फ्रेंचाइजी छोड़ने के लिए संपर्क किया गया है।

राहुल-राशिद खान को लेकर छिड़ी जंग, नई और पुरानी टीमों में खींचतान!

आईपीएल में शामिल होने वाली नयी टीमों की तरफ से राशिद खान और केएल राहुल को लेकर जंग छिड़ती दिखाई पड़ रही हैं। गुप्त रूप से दोनों खिलाड़ियों से टीम में शामिल होने के लिए संपर्क किया गया है। इनसाइडस्पोर्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) और सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) ने आरपीएसजी समूह समर्थित लखनऊ फ्रेंचाइजी के बारे में बीसीसीआई से शिकायत की है कि उन्होंने केएल राहुल और राशिद खान को अपनी फ्रेंचाइजी छोड़ने के लिए दबाव बनाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय बोर्ड अब शिकायतों की जांच कर रहा है।

खिलाड़ी दोषी पाए गये तो लगेगा बैन: बीसीसीआई

बीसीसीआई के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि दो फ्रेंचाइजी से मौखिक शिकायत मिली है कि नई जोड़ी गई लखनऊ फ्रेंचाइजी द्वारा खिलाड़ियों से संपर्क किया जा रहा है। अधिकारी ने यह भी कहा कि अगर यह सच पाया जाता है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। बीसीसीआई अधिकारी ने यह भी कहा कि टीमों के मौजूदा संतुलन को नहीं बिगाड़ना चाहिए। यह कहते हुए कि इस तरह के दृष्टिकोण से बचना मुश्किल है, खासकर जब भयंकर प्रतिस्पर्धा हो, अधिकारी ने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला कि मौजूदा टीमों के लिए यह उचित नहीं है जब खिलाड़ियों से इस तरह से संपर्क किया जाता है। बीसीसीआई अधिकारी ने निष्कर्ष निकालते हुए कहा कि 'हम संतुलन बिगाड़ना नहीं चाहते। जब भयंकर प्रतिस्पर्धा हो तो आप ऐसी चीजों से बच नहीं सकते। लेकिन मौजूदा टीमों द्वारा अगर ऐसा किया जाता है तो कार्यवाई की जाएगी।

क्या छोड़ देनें राशिद खान और केएल राहुल अपनी आईपीएल टीमें

आपको बता दे कि केएल राहुल पहले ही पंजाब टीम को छोड़ने का मन बना चुके थे। वह 2022 के आइपीएल से पहले किसी दूसरी टीम में बतौर कप्तान जा सकते हैं। राहुल अपनी टीम से संतुष्ट नहीं हैं इस लिए दूसरी नयी टीमों द्वारा उनसे संपर्क किया जा सकता हैं लेकिन वर्तमान में जिस टीम में

वह बतौर कप्तान है वह उनके गणित को नहीं बिगाड़ सकते हैं। अगर वह ऐसा कुछ करते हैं तो उनपर एक्शन लिया जा सकता हैं। इसके अलावा राशिद खान ने भी सनराइजर्स हैदराबाद छोड़ना चाहते हैं क्योंकि उनका मानना है कि वह टीम को बतौर कप्तान हेंडल कर सकते हैं इस लिए वह टीम में कप्तान के तौर पर शामिल होना चाहते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद टीम के मौजूदा कप्तान केन विलियम्सन हैं। अब टीम दोनों में से किसे चुनती हैं उसका फैसला होना बाकी हैं।

मई-जून 2022 में नाइनटी-90 बैश लीग किया जाएगा आयोजित

दुबई। दुबई के मंत्री और अमीरात क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) के अध्यक्ष शेख नाहयान बिन मुबारक अल नाहयान द्वारा बताया गया कि नाइनटी-90 बैश अगले साल मई-जून में शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। यह टूर्नामेंट शारजाह क्रिकेट काउंसिल और सेंचुरी इवेंट्स एंड स्पोर्ट्स की साझेदारी में आयोजित किया जाएगा। यह एक बयान में कहा, 90 गेंदों की क्रिकेट लीग को तीन प्रमुख क्षेत्रीय उद्यमियों अब्दुल रहमान बुखारी, एआरवाई ग्रुप के सीईओ सलमान इकबाल और सिनेर्जी ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रबंध निदेशक इमरान चौधरी ने शुरु करने पर विचार किया था। नाइनटी-90 लीग की तैयारी जोरों पर है। शारजाह स्टेडियम के सीईओ खलफ बुखातिर ने कहा, हाल ही में आईपीएल और टी20 विश्व कप में खेलों की मेजबानी करने के बाद, हमने छोटे प्रारूप में बढती रुचि देखी है। इस लिए हम नाइनटी-90 लीग की शुरुआत कर रहे है, जो क्रिकेट प्रशंसकों का ध्यान खींचेगा।

भारत अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रहा : सीएम केजरीवाल

राजेश अलख

नई दिल्ली, 30 नवम्बर । दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोविड-19 के एक नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनजर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है, क्योंकि उनमें से ज्यादातर उड़ानें राजधानी में उतरती हैं।

केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा, 'कई देशों ने ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से आने वाली उड़ानें बंद कर दी हैं। हम देरी क्यों कर रहे हैं? पहली वेव में भी हमने विदेशी उड़ानें रोकने में देरी कर दी थी। अधिकतर विदेशी उड़ानें दिल्ली में आती हैं, दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। पीएम साहिब कृपया उड़ानें तुरंत बंद करें।'

आप नेता ने एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से कहा था, 'दक्षिण अफ्रीका से लौटे एक व्यक्ति चंडीगढ़ में जांच में संक्रमित मिला है। उसके परिवार के सदस्यों में से एक और घरेलू सहायिका भी इस बीमारी से संक्रमित हैं। पॉजिटिव मामलों के नमूने पूरे-जीनोम अनुक्रमण के लिए एनसीडीसी, दिल्ली को कोरोनावायरस का पता लगाने के लिए भेजे जाएंगे।'

दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन के पाए जाने की खबर के साथ, भारत में वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा है कि संक्रमण की नई लहरों की आशंका है और जब तक हम जल्दी और कुशलता से कार्य नहीं करते हैं। देश में संभवत: दोहराई जाने वाली लहरें दिखाई देंगी।

रविवार को, केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि वे उन क्षेत्रों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद करें, जहां इस दौरान कोविड -19 मामलों में बढ़ोत्तरी देखी जा रही है।

इस बीच, दिल्ली सरकार द्वारा संचालित लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल को नए कोविड -19 वैरिएंट ओमिक्रॉन के लिए पॉजिटिव रोगियों के इलाज के लिए नामित किया गया है।

अस्पताल को ऐसे मरीजों को आइसोलेट करने और उनका इलाज करने के लिए वार्ड निर्धारित करने को कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को निर्देश दिया है कि वह किसी भी आधार पर नए वैरिएंट से संक्रमित मरीजों को भर्ती करने से इनकार ना करें।

भारत में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट का कोई मामला नहीं : मंडाविया

नई दिल्ली, 30 नवम्बर (एजेन्सी)। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को राज्यसभा को बताया कि देश में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट का कोई मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए यह टिप्पणी की।

उन्होंने कहा कि देश में कोविड की स्थिति नियंत्रण में है लेकिन इसे और फैलने से रोकने के उपाय किए जा रहे हैं। अब तक पात्र आबादी को कुल 124 करोड़ टीकाकरण की खुराक दी जा चुकी है।

इससे पहले सुबह, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने नए कोविड वेरिएंट के सामने आने के बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने राज्यों को सलाह दी गई है कि वे पॉजिटिव मामलों की शीघ्र पहचान और इसके प्रबंधन के लिए टेस्टिंग में तेजी लाएं।

साथ ही, केंद्र ने 'हर घर दस्तक' अभियान को 31 दिसंबर तक बढ़ाने का निर्देश दिया है, जिसमें 100 प्रतिशत पहली खुराक प्रदान करने और जिन्हें दूसरी खुराक दी जानी है, उन पर भी ध्यान केंद्रित करने को कहा गया है।

राज्यों को शीघ्र पहचान और पर्याप्त स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करने के लिए समय पर परीक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी कहा गया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सोमवार को कहा था कि नए ओमिक्रॉन से संबंधित समग्र वैश्विक जोखिम बहुत अधिक है।

विश्व स्वास्थ्य निकाय ने एक बयान में कहा कि ओमिक्रॉन के अप्रत्याशित तौर पर कई सारे स्पाइक प्रोटीन हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं कि जो संक्रमण का तेजी से प्रसार कर बड़ी आपदा में तब्दील हो सकते हैं। डब्लूएचओ ने कहा कि ओमिक्रॉन उच्च संख्या में उत्परिवर्तन यानी म्यूटेंट पैदा करने की क्षमता रखता है, जिसमें 26 से 32 म्यूटेंट भी हो सकते हैं और इनमें से कुछ चिंता का विषय हैं। वैश्विक स्वास्थ्य निकाय ने कहा कि हालांकि, अभी भी इस नए वैरिएंट को लेकर काफी अनिश्चितताएं हैं।

डब्ल्यूएचओ ने कहा कि वैश्विक स्तर पर ओमाइक्रोन के संभावित प्रसार की संभावना अधिक है। इसने कहा है कि ओमिक्रॉन वैरिएंट पूरी दुनिया में तेजी से फैल सकता है। इसलिए इसने सभी देशों से वैक्सीनेशन में तेजी लाने का अनुरोध किया है। साथ ही सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को इन आपदाओं से निपटने के लिए तैयार करने को कहा गया है।

बीजेपी ने आयोजित किया स्वाभिमान गौरव अभियान

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 30 नवम्बर । बीजेपी की प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से दक्षिण जिले के राबांग्ला स्थित जिला पार्टी कार्यालय में राज्यस्तरीय संविधान गौरव अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह जानकारी दक्षिण जिले के बरफंग के मंडल प्रमुख प्रदीप गुरुंग ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है।

कार्यक्रम में बीजेपी सिक्किम के एससी मोर्चा प्रभारी बिक्रम नस्कर प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम में क्षेत्र विधायक टीटी भूटिया, प्रदेश उपाध्यक्ष अर्जुन राई, एससी मोर्चा अध्यक्ष विरेन्द्र पौराली प्रमुख रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि व अन्य अतिथियों ने डा बीआर अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी और संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया।

नस्कर ने कार्यक्रम को संबाधित करते हुए डॉ. बीआर अम्बेडकर की जीवनी और भारतीय संविधान पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने 26 नवंबर से छह दिसंबर तक देशभर में संविधान गौरव अभियान आयोजित करने का निर्णय लिया है।

इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष अर्जुन राई, बर्फुंग क्षेत्र विधायक एवं सिक्किम प्रदेश अनुसूचित जनजाति के प्राभारी टीटी भूटिया, अनुसूचित जाति सिक्किम प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र पौराली आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

एमएसपी का मुद्दा : केंद्र सरकार बातचीत के लिए राजी, एसकेएम से मांगे 05 नेताओं के नाम

नई दिल्ली, 30 नवम्बर (एजेन्सी)। तीन कृषि कानूनों की वापसी के बाद सरकार एमएसपी और अन्य मुद्दों को पर बातचीत के लिए तैयार हो गई है। केंद्र सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा को बातचीत का प्रस्ताव दिया है। साथ ही किसान संगठनों से पांच नेताओं के नाम मांगे हैं, जो बातचीत के दौरान सरकार के साथ बैठक करेंगे।

किसान नेता दर्शन पाल ने कहा कि एमएसपी और मुद्दों पर पैनल के लिए सरकार ने किसान संघों से पांच नाम मांगे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ( ) चार दिसंबर को होने वाली बैठक में नाम तय करेगा।

वहीं, आंदोलनकारी किसानों के टीकरी बार्डर पड़ाव में मंगलवार को हर तरफ आंदोलन के खत्म होने को लेकर चर्चाएं चलती रहीं। हर तरफ लोग गुफ्तगू करते नजर आए कि आंदोलन जल्द खत्म हो सकता है। लेकिन बार्डर पर हुई सभा में संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के मंच से हर किसान नेता ने कहा कि संगठन का शीर्ष नेतृत्व जो फैसला करेगा, उसका पालन किया जाएगा। वहीं, दिल्ली पुलिस ने बार्डर पर सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए हैं।

इस दौरान मंगलवार को पंजाब किसान यूनियन की प्रधान जसबीर कौर नट ने कहा कि किसानों ने सरकार पर दबाव बनाया है, जिस कारण प्रधानमंत्री को कानून वापस लेने पड़े। हम सभी मांगें मनवाकर यहां से लौटेंगे। बीकेयू पंजाब के लखविंद्र सिंह पीर मोहम्मद ने कहा कि अभी तक हमारा कोई भी फैसला यहां रहने का या जाने का नहीं हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चा जो भी फैसला लेगा।

हम वहीं बात मानेंगे। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन ने पूरे विश्व का भाईचारा बनाया है। किसी को कोई झगड़ा नहीं करना, बल्कि शांति बनाए रखनी है। खुशी मनाओ लेकिन अपने दायरे में रहकर। एडवोकेट मंजीत सिंह भुल्लर ने हमारा किसान भाई तो वापस जाने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार के मन में खोट है। हमें एमएसपी और किसानों को मुआवजा दिया जाए। साथ में जिन किसानों पर मुकदमे दर्ज है उन्हें वापस लिया जाए।

टीकरी बॉर्डर पर किसानों का धरना मंगलवार को भी जारी रहा। तय समयानुसार यहां किसान सभा हुई और अनेक किसानों व नारी शक्ति ने यहां पहुंचकर धरनारत किसानों को समर्थन दिया। सभा को संबोधित करते हुए कई वक्ताओं व किसान नेताओं ने कहा कि किसानों संघर्ष व एकजुटता के चलते उक्त कृषि कानून वापस लिए गए है लेकिन जब तक किसानों की अन्य मांगें पूरी नहीं होती और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आंदोलन को लेकर कोई निर्णय नहीं आता तब तक उनका धरना लगातार जारी रहेगा।

अखिल भारतीय किसान खेत मजदूर संगठन के सचिव जयकरण दलाल के अलावा अनेक किसान नेताओं ने बॉर्डर पर पहुंचकर किसानों को समर्थन दिया। जयकरण ने कहा कि आंदोलन के दौरान 700 किसानों ने जान गवाई है। उन्होंने अपनी शहीदी देकर आंदोलन को आज तक जीवित रखा।

उन्होंने कहा कि दलाल खाप ने भी आंदोलन का शुरू से ही समर्थन किया है। हुड्डा खाप के प्रतिनिधि रमेश हुड्डा ने कहा कि किसानों के एकजुट रहने के कारण यह जीत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने तीन कानून वापस ले लिए हैं। लेकिन जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं मिल जाती हम यहां से नहीं उठेंगे।

जोगेंद्र सिंह नैन बीकेयू जींद ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा जो भी कॉल देगा, उसका हम पूरा पालन करेंगे। मुकदमे वापिस किए जाए। जिन किसानों की आंदोलन के दौरान जान गई है, उन परिवारों को मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी दिल्ली कूच के दौरान जो ट्रैक्टर थानों में बंद है उन्हें छोड़ा जाए। नैन ने किसानों को कहा कि प्रधानमंत्री को जो छह मांगें भेजी गई थी, उस पर फैसले की घड़ी का इंतजार करें और शांति बनाए रखे। नैन ने कहा कि हम अपनी मांगे मनवाने के लिए आए हैं न कि सरकार से टकराने के लिए। राजनीतिक पार्टियां हमें भड़काने की कोशिश करेंगी, लेकिन हमें बहकावे में नहीं आना है। परगट सिंह बीकेयू राजेवाल ने भी सभा को संबोधित किया।

बिहार के विश्वविद्यालयों की वित्तीय अनियमितता की जांच करेगा कैग : शिक्षा मंत्री

पटना, 30 नवम्बर (का.सं.)। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) को राज्य के विश्वविद्यालयों के खातों एवं वित्तीय अनियमितताओं की गहन जांच करने और वस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

चौधरी ने सोमवार को विधानसभा में भोजनावकाश से पूर्व की कार्यवाही के दौरान मुख्य विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के ललित यादव के अल्पसूचित प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि कैग) को राज्य के विश्वविद्यालयों के खातों एवं वित्तीय अनियमितताओं की गहन जांच करने और विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ नर्धारित नियमों के अनुसार कार्रवाई भी शुरू की जाएगी।

मंत्री के जवाब से असंतुष्ट ललित यादव ने कहा कि जब सरकार को विश्वविद्यालय में बड़े पैमाने पर हुई वित्तीय अनियमितताओं की जानकारी थी तो उसे रोकने के लिए पहले ही ठोस कदम उठाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि ऑडिट कराना कैग की एक नियमित प्रक्रिया और कर्तव्य है। उन्होंने सदन की समिति से वश्विद्यालयों की अनियमितताओं की जांच कराये जाने की मांग की। श्री यादव ने मामले की जाचं के लिए विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित करने की भी मांग की। इस पर मंत्री ने कहा कि कैग की जांच संतोषजनक नहीं रहने पर मामले की दोबारा जांच कराई जाएगी।

फिल्मों के माध्यम से विकसित होगा सिक्किम का पर्यटन : लोकनाथ शर्मा

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 30 नवम्बर । स्थानीय खाद्य पदार्थ, संस्कृति-परंपरा और राज्य के पर्यटन गन्तव्य को फिल्मी दुनिया के बड़े परदे पर लाने के लिए राज्य सरकार ने फिल्म पालिसी का निर्माण किया है। जिसके तहत राज्य में किसी फिल्म की 75 प्रतिशत शूटिंग, स्थानीय कलाकारों को अधिक अवसर देने वाले फिल्म निर्माताओं को एक करोड़ रुपये तक की सब्सिडी देने का प्रावधान बनाया गया है। राज्य में चलचित्र पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आगमी 10 से 14 दिसंबर तक सिक्किम ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल-2021 का आयोजन भी किया जा रहा है। 10 दिसंबर को स्थानीय कलाकारों के लिए मंच प्रदान किया जाएगा।

दूसरे सिक्किम ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल को लेकर राज्य सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री लोकनाथ शर्मा ने कहा कि इस कार्यक्रम से स्थानीय कलाकार और सिक्किम को बहुत कुछ फायदा होगा। इस बार राज्य में पहली बार फिल्म निर्माता, निर्देशक और निवेशक सिक्किम आ रहे हैं। बाहर से आए निर्माता, निर्देशक और निवेशक के लिए एक बैठक भी आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया की फिल्म निर्माण करना राज्य में पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देना है।

इसके साथ ही सिक्किम फिल्म प्रमोशन बोर्ड की चेयरपर्सन पूजा शर्मा ने कहा कि ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल मुख्यत: 11 दिसंबर से आयोजित किया जाएगा, जो 14 दिसम्बर तक चलेगा। कार्यक्रम विशेष रूप से राजधानी गंगटोक के मनन केंद्र और एमजी मार्ग में आयोजित किया जाएगा। इसमें लोगों को नि:शुल्क विभिन्न चलचित्र दिखाए जाएंगे, जो सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक चलेगा। इसके बाद म्यूजिकल नाइट का कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि इस फेस्टिवल में स्थानीय कलाकारों के लिए विभिन्न प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम का भी रखे गए हैं।

उन्होंने कहा कि 12 दिसंबर को राजधानी में प्रोड्यूसर एंड इंवेस्टर समिट आयोजित किया जाएगा। चेयरपर्सन पूजा शर्मा के जानकारी के मुताबिक इस अवसर पर मलाइका अरोरा, प्रियदर्शन दर्शन, संजय पूरण सिंह, सयानी गुप्ता जैसी हस्ती बॉलीवुड से सिक्किम आ रहे हैं। इसके साथ ही चर्चित गायक मोहित चौहान भी ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल में भाग लेंगे। वहीं नेपाली फिल्म जगत के प्रख्यात कलाकार भुवन केसी, अनमोल केसी, निखिल उप्रेती, नम्रता श्रेष्ठ आदि भी सिकिक्म आएंगे।

इस अवसर पर सिक्किम से बड़े पर्दे पर दिखने वाली हस्तियों को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड भी प्रदान किया जाएगा।

चेयरपर्सन पूजा शर्मा ने जानकारी दी है कि फेस्टिवल में बालीवुड के ख्यातिप्राप्त कलाकार डैनी डेंजोंग्पा को लेजेंड्री हीरो अवार्ड प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही यहां के श्याम प्रधान, उगेन छोपेल, सानु लामा, प्रशान्त रसाइली, सांतेन भूटिया, दावा लेप्चा, त्रिवेणी राई और कर्मा थाकर्पा को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

बिहार विधानसभा परिसर में मिलीं शराब की बोतलें, तेजस्वी ने सीएम नीतीश कुमार को घेरा

पटना, 30 नवम्बर (का.सं.)। बिहार में शराबबंदी किस कदर विफल साबित हो रही है, उसका उदाहरण मंगलवार को विधानसभा परिसर में ही देखने को मिला। यहां उस समय सनसनी फैल गई जब शराब की कई खाली बोतल मिलीं। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव खुद उस जगह पर गए, जहां शराब की बोतलें पड़ी थीं। तेजस्वी ने इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमले करते हुए उन्हें घेरने की कोशिश की।

तेजस्वी ने कहा कि ऐसे समय जब विधानसभा की सुरक्षा इतनी कड़ी है। तब शराब के बोतलें मिलना साफ़ करता हैं कि बिहार में शराबबंदी नाकाम है। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा परिसर में कितने धड़ल्ले से शराब की बोतल पहुंच गई। अगर बिहार विधानसभा में बोतल पहुंच गई तो सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। जहां सीएम खुद बैठे हैं, वहां से यह स्थान 100 मीटर भी नहीं होगा।

तेजस्वी ने कहा कि बिहार विधानसभा के अंदर शराब की बोतल कहां से आई? मुख्यमंत्री को खुद मुआयना करना चाहिए। शराब माफिया के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर हमने देखी है।

नीतीश कुमार के मंत्रियों को अपराध करने की छूट है। सीएम को बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बेराजगारी, चिकित्सा, पलायन आदि मामलों में इस सरकार ने बिहार को बदनाम कर दिया है।

बिहार में जहरीली शराब से 70 से ज्यादा मौतों को लेकर आलोचना झेल रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में स्वीकार किया था कि राजधानी पटना में शराब बिक भी रही है और लोग पी भी रहे हैं। शराबबंदी के मामले में नीतीश को अपने ही सहयोगी दल बीजेपी की भी आलोचना का सामना करना पड़ा रहा है।

बिहार भाजपा अध्यक्ष और लोकसभा सांसद संजय जायसवाल ने कुछ समय पहले कहा था कि पुलिस की मिलीभगत के बिना राज्य में अवैध शराब की बिक्री नहीं हो सकती। जायसवाल ने कहा कि निश्चित रूप से इस नीति की समीक्षा करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा था कि स्थिति भयावह है। पुलिस प्रशासन की मदद से ही पूर्वी चंपारण क्षेत्र में शराब का कारोबार हो रहा है।

हालांकि नीतीश कुमार ने शराब बंदी को कड़ाई से लागू करने के लिए पिछले हफ्ते कई फैसले भी लिये थे। चौकीदार से लेकर आला अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की गई थीं। लेकिन इस कड़ाई का असर नहीं दिख रहा है।

किसान आंदोलन से अब तक 60 हजार करोड़ के कारोबार का नुकसान : कैट

नई दिल्ली, 30 नवम्बर (एजेन्सी)। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन के बीच आज कैट द्वारा यह जानकारी साझा की गई कि, इस आंदोलन के चलते अब तक करीब 60 हजार करोड़ रुपये के व्यापार का नुकसान हुआ है। कैट ने कहा की, नुकसान के आंकड़े विभिन्न राज्यों से सीएआईटी की अनुसंधान शाखा द्वारा प्राप्त इनपुट पर आधारित हैं।

दरअसल देश भर के विभिन्न राज्यों से प्रतिदिन लगभग 50 हजार ट्रक माल लेकर दिल्ली आते हैं और करीब 30 हजार ट्रक दिल्ली से दूसरे राज्यों में माल ढोते हैं, क्योंकि दिल्ली न तो एक कृषि प्रधान राज्य है और न ही एक औद्योगिक राज्य, इसे अपने सदियों पुराने व्यापार के वितरणात्मक स्वरूप को बनाए रखने के लिए माल की खरीद-बिक्री पर निर्भर रहना पड़ता है और इसलिए दिल्ली किसान आंदोलन का प्रमुख पीड़ित है।

कैट के मुताबिक, नवंबर, दिसंबर, 2020 और जनवरी, 2021 में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से दिल्ली की आपूर्ति पर काफी प्रभाव पड़ा है। वहीं किसानों द्वारा राजमार्ग अवरुद्ध होने के कारण माल की आवक और जावक के परिवहन में कठिनाइयों के कारण यह व्यावसायिक हानि मुख्य रूप से नवंबर, दिसंबर, 2020 और जनवरी, 2021 के महीनों में हुई।

कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि, केंद्र सरकार द्वारा तीन कृषि बिल वापस लिए जाने के बाद किसानों द्वारा आंदोलन जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। किसानों द्वारा दिल्ली की ओर जाने वाले राजमार्गों के अवरुद्ध होने के कारण महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश से माल का परिवहन भी प्रभावित हुआ।

इन राज्यों से आने वाली प्रमुख वस्तुओं में खाद्यान्न, एफएमसीजी उत्पाद, इलेक्ट्रिकल आइटम, बिल्डर्स हार्डवेयर, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो स्पेयर पार्ट्स, मशीनरी लेख, सेनेटरीवेयर और सेनेटरी फिटिंग, पाइप और पाइप फिटिंग, कृषि उपकरण, उपकरण, फर्निशिंग फैब्रिक, कॉस्मेटिक्स, आयरन और शामिल हैं। स्टील, लकड़ी और ख़लाईवुड, खाद्य तेल, पैक्ड सामान्य सामान आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक : सत्येन्द्र नाथ सिंह एवं मुद्रक: नूतन वर्मा द्वारा प्राइम प्रिंटर्स, प्रिमुला कॉटेज, चर्च रोड, गंगटोक से मुद्रित एवं रतना निवास, मेट्रो प्वाइंट, नेशनल हाईवे 10, गंगटोक (पूर्व सिक्किम) से प्रकाशित।
सम्पादक - सत्येन्द्र नाथ सिंह, कार्यकारी सम्पादक - अश्विनी आनंद, मोबाइल नं. : 9474355832, 9609024017, फोन नं. : 03592-204174, पोस्टल रजि. सं. : WB/SKM/110/07-09, e-mail ID : anugamini@gmail.com